OF CULTURE (SHRI D. P. YADAV) : I beg to lay on the Table—

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Salar Jung Museum Board, Hyderabad, for the year 1969-70 along with the Audited Accounts

(ii) A statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the above Report. [*Placed in Library. See* No. LT—1608/72]

(2) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Science, Bangalore and the Statement of Accounts for the year 1970-71. [*Placed in Library. See* No. LT—1609/72.]

(3) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Executive Committee of the Trustees of the Victoria Memorial Hall, Calcutta, for the year 1970-71 together with Audited Accounts. [*Placed in Library. See* No. LT—1610/72.]

———

12.39 hrs.

MOTION OF THANKS ON PRESIDENT'S ADDRESS - *Contd.*

MR. SPEAKER : Now we resume further discussion on the Motion of Thanks to the President.

We have hardly enough time to complete—not hardly, more time rather. The Prime Minister has conveyed to me that she would reply to debate immediately after Question Hour tomorrow.

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur) : That means the time is extended,

MR. SPEAKER : No. Time is not extended. There will be no other motion after the Question Hour, only the Prime Minister will reply.

Mr. Hari Kishore Singh.

श्री हरि किशोर सिंह (पुरी) : अध्यक्ष महोदय, मैं पिछले दिन सदन में चर्चा कर रहा था कि मार्क्सवादी पार्टी का यह आरोप है कि इस देश में गणतंत्र की हत्या हो रही है और पश्चिमी बंगाल में चुनाव के दौरान जो घटनाएं हुई है वह जनतांत्रिक प्रणाली को आगे की ओर बढ़ाने में असफल रही हैं निराधार है । मेरा उन से नम्र निवेदन है कि 1967 के बाद जो घटनाएं हुई और जो हिंसा का वातावरण पैदा किया गया उस से हमारे देश की राजनीति में जनतांत्रिक पद्धति को बढ़ावा नही मिला है । संसदीय जनतंत्र के प्रति जनता में एक तरह से अविश्वास पैदा होता जा रहा था । कांग्रेस हटाओ की एक अंध विरोधी राजनीति कुछ दलों ने पैदा की और उस से देश में एक ऐसा वातावरण पैदा हो गया कि जो भी साधन उपलब्ध हो उन से जैसे भी हो कांग्रेस को पराजित किया जाय । इस नीति ने देश में इस दल बदल की राजनीति को प्रश्रय दिया और जिसके परिणामस्वरूप हमारे देश की क्या हालत हुई है वह सब हम देख चुके है । जो परिस्थितियां उन से पैदा हुई उस से जनता का विश्वास संसदीय राजनीति व्यवस्था में धीरे-धीरे घटता जा रहा है ।

इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहुंगा कि जिस सफलता से प्रधान मंत्री ने 1971 में इस देश को नेतृत्व दिया और जिस जोरदार तरीक़े से देश की जनता ने प्रधान मंत्री के हाथ मजबूत किये उसने एक नई राजनीति को जन्म दिया है और संसदीय जनतंत्र में जनता का पुनर्विश्वास उत्पन्न होने लगा है और यह आशा हो गई है कि शायद जनतांत्रिक पद्धति द्वारा समाज का कल्याण हो सकेगा । इस सम्बन्ध में मैं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे जो पश्चिमी बंगाल के वर्तमान विधान सभा का बहिष्कार कर रहे हैं वह संसदीय जनतंत्र की अमर्यादा है और वे ऐसा करके संसदीय जनतंत्र की पद्धति कोई बल नहीं दे रहे हैं । मेरा उन से अनुरोध होगा कि वह एक समझदार व सशक्त पार्टी के सदस्य हैं, अपने बहिष्कार को त्यागें और जनतांत्रिक प्रणाली की जो प्रमुख धारा है उस में शामिल होकर संसदीय जनतंत्र को सफल बनायें ।

[श्री हरि किशोर सिंह]

अध्यक्ष महोदय, जो दूसरी प्रमुख घटना पिछले साल हुई वह बगला देश के सम्बन्ध मे थी। बगला देश की घटना इस देश के इतिहास मे ही नही अपितु सारे मानव इतिहास मे एक अलौकिक घटना है। सारा देश बगला देश की घटना से प्रभावित रहा। जो नीति भारत सरकार द्वारा बंगला देश के सम्बन्ध मे अपनाई गई वह एक राष्ट्रीय नीति थी। बगला देश के सम्बन्ध मे भारत सरकार की नीति का इस सदन ने सर्वसम्मति से समर्थन किया था और इसलिए आज जब जनसघ के साथी बगला देश के सम्बन्ध मे अपनाई गई नीति की आलोचना करते हैं तो बात समझ से नही आती है। बगला देश के सम्बन्ध मे सरकार को क्या निर्णय लेना चाहिए था यह सरकार के लोग जानते थे। बगला देश के सम्बन्ध मे भारत सरकार द्वारा अपनाई गई नीति का जो परिणाम हुआ वह हम सबके सामने मौजूद है और इसलिए आज उस पर नुक्ताचीनी करना उस नीति की सफलता को गौण करना होगा।

बगला देश के सम्बन्ध मे आज एक विषाक्त प्रचार विदेशो मे चल रहा है और वह यह कि बगला देश की ओर भारत की दृष्टि लगी हुई है। इस सम्बन्ध मे मै विदेश व्यापार मंत्री की उस घोषणा की सराहना करता हूँ जिसमे उन्होने कहा है कि बंगला देश के साथ जो भी हमारा व्यापार होगा वह भारत सरकार द्वारा होगा। स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन उसे करेगी और यहा के व्यापारियो को बगला देश के साथ निजी तौर पर व्यापार करने की अनुमति नही दी जायेगी। हा, अगर बगला देश की स्वतंत्र सरकार वैसा चाहेगी तो ऐसा मौका मिलेगा। परन्तु सरकार से मेरा अनुरोध होगा कि बगला देश से सम्बन्धित जितने भी व्यापारिक निर्णय हो और जितनी भी कार्यवाही हो वह सरकारी स्तर पर होनी चाहिए। व्यापारियों को बगला देश से सीधे व्यापार करने का मौका नही देना चाहिए क्योंकि उस से हमारे और बगला देश के मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध मे कुछ गतिरोध पैदा हो सकता है, कुछ गलतफहमियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। सम्भव है कि व्यापारी अपने मुनाफे की मनोवृत्ति की वजह से बगला देश के अच्छे भले लोगो को शोषण करना चाहे। इसलिए मेरा नम्र निवेदन है कि बगला देश के साथ जो भी हमारी व्यापारिक नीति हो, जितने कारोबार हों वह सरकारी स्तर पर होने चाहिए, निजी तौर पर सीधे व्यापारियो द्वारा नही होने चाहिये।

दूसरी चीज जो बगला देश के सम्बन्ध मे उत्पन्न होती है वह यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय पैमाने पर खास तौर पर एशिया के छोटे छोटे मुल्को मे साम्राज्यवादी शक्तियो द्वारा यह प्रचार किया जा रहा है कि भारत की बगला देश के बाद दूसरे छोटे छोटे पडोसी राष्ट्रो पर नजर है और उनको वह किसी न किसी तरह से अपने प्रभाव क्षेत्र मे रखना चाहता है। यह सर्वथा गलत है। इस आरोप का इस सदन मे जोरदार खण्डन होना चाहिये। इस बात का बहुत बार स्पष्टीकरण किया गया है कि हम किसी भी देश के ऊपर शक्ति-प्रभाव नही चाहते है न तो हम प्रभाव क्षेत्र की राजनीति मे विश्वास ही करते है। हमारी वैदेशिक नीति की आधारशिला श्री जवाहरलाल नेहरू के जमाने मे रखी गई थी और वह आपसी सहयोग और पारस्परिक सद्भावना की नीति है। हम एक दूसरे के विकास मे मदद देना चाहते है। हमारी कोई भी इस तरह की नीति नही होगी जिससे कि हमारे पडोसी देशो को किसी भी तरह हमारी बगला देश सम्बन्धी नीति मे कोई आशका हो।

बगला देश के सम्बन्ध मे चर्चा करते हुए अपने देश के पिछडे और अविकसित इलाको की चर्चा करना आवश्यक है जिनकी कि आर्थिक परिस्थिति बहुत कुछ बगला देश से मिलती है। यह नही कि बगला देश मे जो पाकिस्तान ने किया उससे इस नीति का कोई सम्बन्ध है। लेकिन अपने देश के जो पिछडे इलाके है उनकी बहुत ही गम्भीर स्थिति थे और मैं इस सम्बन्ध मे चाहूँगा कि सरकार उस का एक सर्वेक्षण कराये कि इस देश के जो पिछडे इलाके है उनकी 1950 मे क्या स्थिति थी और आज 1972 मे क्या है। 1950 और 1972 की स्थिति में कुछ

फर्क पड़ा है या नहीं। इस बारे में जो पिछड़े इलाके और उन्नतिशील इलाके हैं उनका एक तुलनात्मक सर्वेक्षण होना चाहिए। यहा पर मुझे दु.ख के साथ कहना पड़ता है कि 1950 और 1972 के बीच तुलनात्मक सर्वेक्षण से पता चलता है कि स्थिति यथावत है और उसमे सुधार नही हो पाया है तो यह हमारी नीति की त्रुटि की वजह से ही है। यह सुनियोजित नीति के अभाव के कारण है। हमारी धारणा थी कि औद्योगीकरण के द्वारा यह जो पिछड़े इलाके है वह विकसित हो जायेंगे और देश के उन्नतिशील इलाको के मुकाबले मे आ जायेंगे। इसलिए हमने इन पिछडे इलाको मे जो कि प्राकृतिक साधनो मे भरपूर है, बडे-बडे उद्योग लगाये है मेरे स्वयं के प्रान्त बिहार मे कोई 650 करोड रुपया केन्द्रीय सरकार का लगा हुआ है लेकिन उस से क्या फर्क हुआ। भारी उद्योगो के ये स्थल समृद्धि के द्वीप मात्र है उनका वहा के जनजीवन पर, वहा की सामाजिक व्यवस्था और वहा के रहने वालो की आर्थिक स्थिति पर कोई प्रभाव नही पडा है। इसलिए मेरा अनुरोध होगा कि पिछडे इलाको के आर्थिक विकास की जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार ले। मैं तो यहा तक कहने के लिए तैयार हूँ कि जिस प्रकार राज्यों मे सवैधानिक व्यवस्था की कमी आ जाती है, कास्टीट्यूश्नल ब्रेकडाऊन हो जाता है और राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है उसी रूप मे इन पिछडे इलाको में, जहा आर्थिक दृष्टि से राज्य प्रशासन की विफलता रही है, केन्द्रीय सरकार वहा के आर्थिक विकास की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ले। इस सम्बन्ध मे मैं यह सुझाव देना चाहूगा कि इसके लिए एक बैकवर्ड रीजन डेवलपमैंट एथारिटी का गठन होना चाहिए और इस के माध्यम से हम प्रत्यक्ष रूप से केन्द्र द्वारा इन पिछड़े इलाको का विकास करें। इस सम्बन्ध मे मैं सुझाव देना चाहूगा कि भविष्य मे बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठान स्थापित करने के साथ-साथ एसलरी इंडस्ट्रीज एव लघु उद्योगों की स्थापना एव विकास की भी व्यवस्था की जाय। साथ ही जब तक इन इलाकों में कृषि का आधुनिकरण नहीं होगा तब तक आर्थिक दृष्टि से ये इलाके पिछड़े ही रहेंगे। इसलिए यह आवश्यक है कि भूमि सुधार की दिशा में शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाई हो और किसानों को कृषि सम्बन्धी सुविधायें बड़े पैमाने पर दी जायें। इस सम्बन्ध में कृषि के क्षेत्र में सरकारी ऋण नीति में बुनियादी परिवर्तन आवश्यक है। किसानों को प्राथमिकता के आधार पर 4% दर पर व्यापक तौर पर कर्जा मिलना चाहिये।

अब मैं अपने इलाके के बारे में दो तीन बातें कहना चाहता हू। बिहार का उत्तरी हिस्सा बहुत ही पिछडा हुआ क्षेत्र है। वहां पर दो एक योजनाये केन्द्रीय सरकार की ओर से चल तो रही है। लेकिन मैं कहना चाहता हू कि बागमती योजना को शीघ्रातिशीघ्र कार्यान्वित किया जाए। साथ ही अधवार नदी समूह की भी योजना जल्द बनाई जाए।

दूसरी चीज मैं यह कहना चाहता हूँ कि उत्तरी बिहार का इलाका यातायात की दृष्टि से बहुत पिछडा हुआ है। बाढ की वजह से हर साल वहा की सडके नष्ट हो जाती है। रेल के माध्यम से जो यातायात की सुविधा वहां उपलब्ध है वह छोटी लाइन होने की वजह से पर्याप्त नही है। मैं चाहता हूँ कि पूरे उत्तर बिहार में बडी रेल लाइन की व्यवस्था हो। खास तौर पर समस्तीपुर से नहरकटिया गंज तक, दरभगा और सीतामढी होते हुए जो लाइन जाती है उसको बड़ी लाइन मे शीघ्र परिवर्तित कर दिया जाए। इसी प्रकार से मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए नेपाल की सीमा तक जो सडक जाती है, हमारे समदीय विभाग के मत्री जानते है कि वह सड़क कितनी महत्वपूर्ण है, उसको राष्ट्रीय मार्ग का दर्जा दिया जाए और केन्द्रीय सरकार की ओर से उसका निर्माण कराया जाए।

इन्ही शब्दो के साथ मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा गया है, उसका समर्थन करता हूँ।

SHRI MALLIKARJUN (Medak) : I pay my homage to the martyrs of the Indo-Pakistan war and of the Telengana movement and

[Shri Mallikarjun]

express my condolences to their bereaved families. Coming to the President's Address, as has been mentioned by the President, the Government's commitment is to achive prosperity and progress in agriculture, industry and in the educational and other fields. This commitment has been discharged to the extent it has been discharged, satisfactorily. The Government's policy in adopting rural and agricultural ceilings as recommended by the Central Committee on land reforms and in providing water, electricity and credit facilities to the farmers is worthy of appriciation. The functioning of the Rural Electrification Corporation with an outlay of Rs 106 crores, particularly by advancing already Rs. 43 crores to the backward areas is a matter for satisfaction for the farmers. At the same time, the output of small scale industries has been raised by providing adequate raw materials and liberal import facilities. Every calory of the energy of our beloved Prime Minister is dedicated to the eradication of poverty, ignorance and unemployment and to build a socialist, secular democratic society. This is something unparalleled in modern history. Sir, the very national policy to transform the socio-economic structure and to aid in various ways for the progress and prosperity and the uplift of the common people in this country is admired by 55 crores of people in this country and the people elsewhere

However, in this connection, the President has not made any mention regarding Telengana. The entire House is conscious of the fact that the Telengana movement for the creation of a separate Telegana State was started on the 15th January, 1969. It was the experience, it was the observation of everyone of us that in that agitation lakhs of people offered satyagraha and adopted the Gandhian principles of truth and non-violence to achieve their cherished object. However, the Telengana Praja Samiti which was running this movement has been culminated and merged with the Congress (R) without any agreement. But long back, in 1956, there was an agreement which was signed by the then agitators. Today, there has been no signature. It was the spirit of confidence between the Prime Minister and the Praja Samiti leaders and the people of Telangana in general. With that same confidence today we anticipate that the Prime Minister and her Government will definitely adopt adequate steps which are required for the fulfilment of the aspirations of the people.

However, in this movement, I have to mention that the politicians have appeared and disappeared and I have been painted with a political colour, but still, the people's feelings have remained ; the people's aspirations have to be fulfilled only by our beloved Prime Minister and nobody else. With our faith and trust and immense confidence in the Prime Minister, we feel that she will definitely do it. Unfortunately, the judgement of the full Bench of the Andhra Pradesh High Court has been so unsatisfactory to the people, as also the formula, or whether it is, which was evolved as a consequence of the negotiations between the Prime Minister and the Telengana Praja Samiti.

Today, what we need is a constitutional amendment for the implementation of the Mulki rules which is absolutely indispensable in order to create satisfaction, in order to give contentment to the people of Telengana. We have agitated, and we have given the mandate in the last mid-term poll for the Telengana Praja Samiti to create a separate Telegana State. Later, as a result of the intervention of our Prime Minister, following the national policy, they have also given the mandate to the Prime Minister. Now, today, it is the responsibility of the Prime Minister to look into the affairs and to realise that our objective was not to replace Mr. Brahmananda Reddy with another Telengana Chief Minister but that it is a matter of our genuine feelings. So, when two mandates have been given as we have belief in our beloved Prime Minister, it necessitates the Prime Minister, since she is also present in the house, to adopt constitutional measures for the implementation of the Mulki rules.

Some people feel that it may affect some Andhra personnel. Nothing of the sort. Supernumerary posts can be created and an amicable and peaceful atmosphere can be created.

13 hrs.

Finally, without consuming much time of the House, with all reverence to the Prime Minister, all faith in the Prime Minister, I wish to lay emphasis only on one point, and that is, the need of the hour for the Telengana

people is the consitutional amendment for the implementation of the Mulki rule. Or-else, the only alternative left for the Prime Minister is to create a separate Telengana State, by bifurcating the Andhra Pradesh State in the interests of the people. In the interests of the people, who have given the mandate in a dual manner.

Now it is the responsibility of the Prime Minister People's feelings in a democratic set up cannot be ignored. I therefore appeal to the Prime Minister to adopt constitutional measures immediately in order to satisfy the people who have given her a mandate on national policy for the eradication of ignorance and poverty. Finally, with faith and trust and confidence in the Prime Minister and with all anticipation, I think salvation can be achieved.

MR SPLAKER : Shri Kushok Bakula He may speak after lunch

---

13 02 hrs.

The Lok Sabha adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

The Lok Sabha re assembled after Lunch at five minutes past Fourteen of the Clock.

[MR DEPUTY-SPEAKER *in the Chair.*]

MOTION ON THANKS ON PRESIDENT'S ADDRESS – *Contd.*

श्री कुशोक बाकुला (लद्दाख) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा करते हुए यह कहना चाहता हूँ कि जम्मू-काश्मीर-लद्दाख हिन्दुस्तान का अंग है, कोई दूसरा इसके बारे में फैसला नहीं कर सकता, सदर भुट्टो चाहें जो कहे, निक्सन चाहें जो कहें, चू० एन-लाई चाहे जो कहे, लेकिन हमारा जम्मू-काश्मीर-लद्दाख 1947 में भारत के साथ विलय किया, भारत में एक्सीड किया, अब भारत का अटूट हिस्सा है, जैसे हिमाचल प्रदेश है और दूसरे राज्य है। मैं प्रधान मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि 1972 में राज्यों की विधान सभाओं के जो चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस को बहुमत मिला, उससे यह स्पष्ट हो गया है कि भारत की 55 करोड़ जनता इन्दिरा जी के नेतृत्व में काम करना चाहती है और लोकतंत्र, समाजवाद और धर्मनिर्पेक्षता में विश्वास करती है।

अभी भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ, उस में जम्मू-काश्मीर और लद्दाख में जितनी चौकिया हम ने कब्जे मे ली है, उनको देखते हुए अब पाकिस्तान हमारा कुछ नही कर सकता। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा प्रधान मत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि वे जब भी युद्ध विराम के बारे में बातचीत करे, वे इस बात का ध्यान रखें कि जो चौकिया हमने ली है, उनको हमे नही छोड़ना चाहिये। 1965 की लडाई मे हमारे लद्दाख क्षेत्र की एक सबसे बड़ी और ऊची चौकी "कारगिल" हम ने ली थी, यह 13 हजार फुट की ऊचाई पर है, हमारे जवानो ने बड़ी मेहनत से इस को जीता था, लेकिन ताशकन्द समझौते के तेहत हम को उसे वापस करना पड़ा था। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि इस वक्त जो बहुत सी चौकिया हमारे पास है ऐसा न हो कि हमें उन को वापस देना पड़े। अगर ऐसा हुआ तो इस से जनता भी नाराज होगी और हमारे भविष्य के लिए भी अच्छा नही होगा।

दूसरी बात मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि एटम बम बनाने के लिये भी हमें फिर से विचार करना चाहिये। हम लड़ाई नही चाहते है, हम शान्ति से रहना चाहते है और हिन्दुस्तान हमेशा शान्ति से रहता आया है, लेकिन आज चीन और अमरीका जो बातचीत करते है, सदर निक्सन और चू० एन-लाई जो बातचीत करते है, उस से ऐसा अन्दाज़ा लगता है कि वे भारत को कमजोर करना चाहते है, लेकिन मेरा पूरा यकीन है कि भारत को कोई भी कमजोर नहीं कर सकता। इस में कोई शक नही कि भारत के पास अणु बम से भी अधिक शक्ति है क्योंकि भारत की जनता प्रधान मंत्री जी में अटूट विश्वास करती है, लेकिन फिर भी कुछ लोग कहते है कि भारत के पास अणु बम

[श्री कुशोक बाकुला]

नही है। मै ऐसा विश्वास करता हूं कि या तो विश्व में किसी भी देश के पास अणु बम न हो, कोई उस को न बनाये और जो बने हुए हैं, उन का किसी न किसी तरह से नाश कर दिया जाय और फिर आगे से कोई न बनाये। ऐसा राष्ट्र संघ में तय हो जाय, लेकिन यदि ऐसा नहीं होता तो कोई देश बनाये और भारत न बनाये तो इस से कोई लाभ नही होता है, फिर उस के कोई अर्थ नही रहता है।

तीसरी बात मै प्रधान मत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं लेकिन मुझे अफसोस है कि प्रधान मंत्री जी यहां उपस्थित नही है कोई दूसरे मंत्री भी यहां नोट करने वाले नही है। मेरा निवेदन यह है कि तिब्बत के बारे में, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण मे सन् 1967 से सुनता आ रहा हूं, उसमें कोई उल्लेख नही होता है और न ही विरोधी दल या कांग्रेस दल के लोग तिब्बत के बारे में कोई बात करते है। मै यह नही कहता कि तिब्बत के बारे में कोई लड़ाई करनी चाहिए लेकिन फिर भी कुछ सोचना तो अवश्य चाहिए। तिब्बत के चीन के कब्जे मे आ जाने से ही भारत के सामने मुसीबत खड़ी हुई है। कई समत्सदस्य लद्दाख की तरफ गए है और उन्होने वहा पर देखा है कि करीब 150 मील दूरी पर चीन बैठा हुआ है। इस समय तो चीन शान्ति से बैठा हुआ है लेकिन वह किसी भी समय गड़बड़ कर सकता है क्योकि सदर निक्सन और चाऊ एनलाई की बातचीत हुई है और वे भारत को कमजोर करना चाहते है। यद्यपि वे भारत के खिलाफ कुछ कर नही पायेगे परन्तु फिर भी परेशान कर सकते है। एक तरफ तो भुट्टो साहब कश्मीर में गुरिल्ला भेज कर गडबड़ करा सकते हैं और दूसरी तरफ लद्दाख और नेफा की ओर से चीन परेशान कर सकता है। इसलिए मै समझता हूं तिब्बत के बारे में कुछ बातचीत जरूर होनी चाहिए। मै प्राइम मिनिस्टर से निवेदन करता हूं कि मुझे उत्तर चाहिए कि तिब्बत के बारे में भारत का रवैया क्या है?

हम चाहते हैं कि चीन के साथ हमारी दोस्ती हो लेकिन हमारे विदेश मंत्री, सरदार स्वर्णसिंह ने कई सदस्यों के सवाल पूछने पर बताया कि जब वक्त आयेगा तब हम तिब्बत के बारे में कुछ करेगे तो मैं जानना चाहता हूं वह समय कब आ रहा है, यह स्पष्ट होना चाहिए। तिब्बत में लाखों आदमियों की नस्ल खत्म की जा रही है। धर्म की बात छोड़ दीजिए, उन तमाम लोगों को ही खत्म किया जा रहा है। वहां की कला, संस्कृति और इतिहास को समाप्त किया जा रहा है। तिब्बत के बारे में अगर भारत सरकार कुछ करना चाहती है तो वह पूरे तिब्बत के खत्म होने के बाद करना चाहती है या उससे पहले करना चाहती है? मै मानता हूं कि एक दम से कोई वैसा कदम नही उठाना चाहिए लेकिन फिर भी कुछ सोच विचार तो होना ही चाहिए। पहले श्री स्वर्णसिंह जी कहा करते थे कि चीन राष्ट्रसघ का सदस्य नही है लेकिन अब तो चीन राष्ट्रसंघ का सदस्य भी बन गया है। इसलिए अब भारत का रवैया क्या है? मै भारत सरकार को बहुत धन्यवाद देता हूं कि दलाई लामा और हजारो की तादाद मे उनके शिष्यो ने जो भारत मे शरण ली है वह वहां पर बड़े आराम से बैठे हुए है। इस के लिए बहुत आभारी हू लेकिन मै इनसे भी ज्यादा लाखो की तादाद मे लोग तिब्बत मे मुसीबत मे पड़े हुए है। बंगला देश को जो आपने सहायता दी वह बहुत अच्छा किया लेकिन तिब्बत के बारे में कुछ न कुछ सोचना चाहिए। इस सम्बन्ध में मै इतना ही अर्ज करना चाहता हूं।

राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में शिक्षा के सम्बन्ध मे पिछड़े इलाकों का उल्लेख किया है और उन्होने कहा है कि जो पिछड़े इलाके है उनकी तरफ ज्यादा ध्यान दिया जायेगा। लेकिन आप जानते हैं कि लद्दाख सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है। आर्थिक, सामाजिक तथा शिक्षा, सभी क्षेत्रों में लद्दाख सबसे पिछड़ा हुआ है। अब शिक्षा क्षेत्र में वहां पर थोडी बहुत तरक्की हुई है वर्ना पहले वहां कुछ भी नहीं था। इस तरफ वहां पर और भी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है।

आजकल हमारे जम्मू कश्मीर के जो मुख्य मंत्री सैयद मीर कासिम हैं वे बहुत शक्तिशाली आदमी हैं। मैं यहां पर संसत्सदस्यों को बताना चाहता हूं कि वे वहां कोई गड़बड़ी नहीं होने देंगे। जम्मू कश्मीर के लोगों को उन पर पूरा भरोसा है। विशेषकर लद्दाख के लोग मुख्य मंत्री सैयद मीर कासिम पर पूरा भरोसा करते है। लेकिन साथ-साथ आपकी सहायता भी होनी चाहिए। हमारे लद्दाख में 1969-70 से पानी की बहुत कमी हुई है। वहां बारिश तो होती नही — केवल साल मे एक इंच बारिश होती है। वहां पर जो बर्फ पड़ती थी वह बर्फ भी आजकल नही पड़ रही है सर्दियों मे, इसलिए पानी की बड़ी कमी हो गई है। ऐसी हालत मे वहा विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

मैं प्रधान मंत्री जी का आभारी हूं दिन रात देश विदेश के मसलों मे व्यस्त रहते हुए भी वे दो बार लद्दाख आई और सारी बाते देखी लेकिन केन्द्रीय सरकार का कोई भी मिनिस्टर वहां पर नही आया। केन्द्रीय सरकार के मिनिस्टरो को भी वहां आना चाहिए और देखना चाहिए। मुझे बड़ा अफसोस है कि जम्मू कश्मीर से तीन मिनिस्टर केन्द्रीय कैबिनेट में बैठे हुए है लेकिन उनमे से कोई भी लद्दाख नही आया। क्या लद्दाख जम्मू-कश्मीर के साथ मे नही है? तो वहा पर मिनिस्टरो को आना चाहिए और देखना चाहिए। वहा पर खाद्यान्न की बड़ी मुश्किल है। मैं राज्य सरकार का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने बहुत सा अनाज वहा पर भेजा, जानवरों के लिए घास भी भेजी लेकिन वहां के लोग इस राशन और घास को लेकर कब तक रहेंगे? मेरी प्रार्थना है कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट की तरफ से वहा पर कोई दल भेजा जाना चाहिए जोकि जाकर सारी चीजो को देखे। वहाँ पर चार पांच बड़ी बड़ी दरियाये बहती है, उनको प्लान बनाकर उपयोग मे लाने की जरूरत है। वहां पर जापान के पंप्स पावरलेम की बहुत जरूरत है क्योंकि पानी की बहुत कमी है। इसी तरह से वहा पर बिजली की भी बहुत कमी है। उसके लिए भी योजना बनाने की जरूरत है।

हमारे लद्दाख मे लेह, कारगिल और जंस्कार तहसीले है। जंस्कार तहसील में अभी कोई भी तरक्की नही हुई है। कारगिल मे पनबिजली की योजना होनी चाहिए। मैंने बार-बार इस सदन मे अर्ज किया है कि लेह मे स्तकना पनबिजली प्रोजेक्ट बना है लेकिन उसका काम बहुत धीमा है, उसमे तेजी लानी चाहिए।

इसी तरह से लद्दाख के लोग शिक्षा का बहुत शौक रखते है लेकिन उनको वजीफा नही मिलता है। वजीफा मिलता भी है तो बहुत कम मिलता है। उनको वजीफा ज्यादा मिलना चाहिए। वहा के लोगो को भी अगर आप तरक्की की तरफ ले जाये तो बहुत अच्छा होगा। जहा पर तरक्की हुई है वहा पर और तरक्की करनी चाहिए, इसमे कोई हर्ज नही है लेकिन जहा पर आज तक कुछ भी नहीं हुआ है वहा पर कुछ न कुछ करना बहुत ही जरूरी है।

इसी तरह से मेरी प्रार्थना है कि डिस्ट्रिक्ट लद्दाख को शेड्यूल्ड ट्राइब्ज और शेड्यूल्ड एरिया मे लेना चाहिए। जो बार्डर एरियाज है जैसे चागथाग और जो दूसरे क्षेत्र है उनको शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड एरिया मे लेना चाहिए।

इसी प्रकार से जो लद्दाख की भाषा है उसको बोलने वाले देश मे पांच लाख लोग है। सिक्किम, भूटान और तिब्बत के लोग सभी इसी भाषा को बोलते है। इसके लिए मैं ने पहले भी अर्ज किया था कि संविधान की अनुसूची मे 19वीं भाषा के रूप मे इसे शामिल करना चाहिए। जम्मू और कश्मीर राज्य मे यह मान्यता-प्राप्त भाषा है। मैं चाहूंगा कि लद्दाख मे इन सब बातो की तरफ विशेष ध्यान दिया जाये।

श्री सुधाकर पांडे (चंदौली) : उपाध्यक्ष जी, मै राष्ट्रपति जी के भाषण और उसमें उल्लिखित जो विकास मूलक तत्व हैं उनका अभिनन्दन करता हूं। सारे देश की जनता ने समाजवाद के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया है और देश मे समाजवाद के लिए एक भावोदय हुआ है। भाव का उत्पन्न होना सामान्य बात नहीहै

[श्री सुधाकर पांडे]

किन्तु उसके लिए भाषा की अपेक्षा होती है। यद्यपि श्री अच्युत पटवर्धन जैसे विचारक मानते हैं, अभी हाल में कल परसों की बात है, उन्होंने काशी में सार्वजनिक रूप से कहा हैं कि वर्तमान दलों में यदि कोई दल सर्वाधिक समाजवादी दल इस समय देश में है तो वह कांग्रेस ही हैं। जब समाजवादी दल की कांग्रेस में स्थापना हो रही थी 1936 में, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संदेश भेजा आचार्य नरेन्द्र देव जी और जय प्रकाश नारायण जी के नाम यदि समाजवाद आना है, तो जनता की भाषा का उपयोग और प्रयोग करना होगा परन्तु हमारा दुर्भाग्य यह रहा है कि स्वतंत्रता के बाद शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र पर जितना ध्यान देना चाहिए था उतना नही दिया गया। कोई भी देश प्रगति नहीं कर सकता, कोई भी देश उन्नति नहीं कर सकता और वहां समाजवाद भी नही आ सकता है यदि उस की अपनी भाषा नहीं होगी और उस की अपनी कोई संस्कृति नहीं होगी। इस देश की संस्कृति सदा से समाजवादी रही है क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है जो सदा से भेद में अभेद देखता रहा है। यह हमारी संस्कृति की मूल चेतना है और इस संस्कृति की चेतना को कुछ सम्प्रदाय वाले कुछ हिन्दू के नाम पर और कुछ मुसलमान के नाम पर संकीर्ण करते रहे हैं। साम्प्रदायिकता संकीर्णता की भावधारा है क्योंकि जहां संकीर्णता होगी वहां अगति होगी, जहां संकीर्णता होगी वहां पर मृत्यु की उपासना होगी। जीवन की उपासना वहां होती है जहां अभेद की दृष्टि होती है, जहां अभेद की जय होती है। अभेद की दृष्टि तब तक नहीं प्रवर्द्धित हो सकती है जब तक कि सांस्कृतिक पक्ष की ओर ध्यान न दिया जाए, किन्तु यह दुर्भाग्य रहा है देश का कि 25 वर्षों के भीतर हम कोई स्पष्ट शिक्षा नीति नहीं अपना पाए। यही एक ऐसा विषय है कि जितने भी आयोग बने चाहे वे राज्य स्तर पर बने हों, चाहे भारतीय सरकार के स्तर पर, चाहे आचार्य नरेन्द्र देव आयोग रहा हो और चाहे वह सम्पूर्णानन्द कमीशन रहा हो, चाहे वह राधाकृष्णन कमीशन रहा हो और चाहे कोठारी साहब कमीशन रहा हो, किसी भी कमीशन की बात नहीं पूरी सुनी गई और किसी भी कमीशन की बात को पूर्णतः कार्यान्वित नहीं किया गया है, उनकी जो उपलब्धियां हैं उनको कार्यान्वित नहीं किया गया है।

गांवों में जब हम जाते हैं तो यह देखते हैं कि प्राइमरी पाठशालाओं की यह स्थिति हो गई है कि उन में जानवर और चिड़ियां भी चैन से नहीं रह सकते। पेड़ों पर बने घोंसले अधिक अच्छे हैं अपेक्षाकृत उन प्राइमरी पाठशालाओं और उन स्कूलों के जिन में भावी भारत के भविष्य विधाता और कल जो भारत के भविष्य-विधाता होने वाले हैं, शिक्षा प्राप्त करते है। यह सही है कि यह विषय राज्य का विषय है किन्तु हम यह जानते है कि जहां भी प्रगति में कोई चीज बाधक होगी, चाहे राज्य प्रगति मे बाधक हो या व्यक्ति प्रगति में बाधक हो, या दल प्रगति में बाधक हो, उस अवरोध को हमें हटा देना चाहिए यदि हम वास्तव में समाजवादी है। यदि आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षा को केन्द्र का विषय होना चाहिए तो उसके बनाने मे किसी प्रकार की चिन्ता नहीं करनी चाहिए, किसी प्रकार की परवाह नहीं करनी चाहिए और निश्चय ही जो हमारे नौनिहाल हैं उनके लिए शिक्षा के क्षेत्र में ओजस्वी ढंग से कार्य करना चाहिए।

क्रेश प्रोग्राम में कुछ प्राइमरी पाठशालाओं के लिए कुछ किया जा रहा है और हमारे घोषणा पत्र में भी प्राइमरी पाठशालाओं के लिए कुछ कहा गया है लेकिन वह जलते तवे पर जल छिड़कने मात्र है और उस से कोई काम नहीं होने वाला है।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि समाजवाद हमें लाना है माध्यम की पवित्रता की बात गांधी जी भी कहते थे और हम लोग भी कहते हैं लेकिन जिस मशीनरी के माध्यम से समाजवाद ले आना है उस से एक नहीं हजार वर्ष तक भी हम लोग समाजवाद का नारा देते रहें तो वह भी माध्यम कभी भी किसी प्रकार समाजवाद नहीं लाने देगा। वह जनता के बीच में मध्यस्थता

(दलाली) कर के हमारी आर्थिक प्रगति को रोके हुए है। सरकारी कर्मचारियों का जो तंत्र है, जो यंत्र है वह तंत्र और यंत्र हमारी प्रगति से मूलतः बाधक है क्योंकि योजना बनाने मे हम उन की सलाह लेते हैं लेकिन जब कार्यान्वयन की बात आती है तो उस का कार्यान्वयन कभी नही होता है और उस का परिणाम यह होता है कि दिनोत्तर व्यय भार योजना पर बढ़ता जाता है और बहुत सी योजनाओं के व्यय-भार बढ़ने के कारण हमारा गरीब देश साधन उपलब्ध नही कर सकता है। उसका परिणाम यह होता है कि हमारी योजनाएं खटाई मे पड़ जाती है और जो प्रगति होनी चाहिए वह प्रगति नहीं हो पाती। जब हमारे भीतर किसी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं है तो जो अवरोध किसी भी प्रकार हमारे रास्ते मे आता है उस अवरोध को समाप्त करने में किसी प्रकार भी हमे हिचकना नही चाहिए। किसी प्रकार की चिन्ता नही करनी चाहिए, नही तो 1967 मे जिस तरह से जनता ने आक्रोश दिखलाया था हमारे ऊपर और विरोधियों ने समझ लिया था कि जनता का उन्हें प्यार प्राप्त हो रहा है तथा वे जनता के भाग्य विधायक हो गये है, उसी प्रकार का धक्का 1976 मे फिर से खाना पड़ सकता है। इसलिए मैं शासन से निवेदन करना चाहता हूँ क्योकि शासन अपना है, देश की जनता का है कि इस टी० बी० के कीटाणु से देश की जनता की रक्षा करनी चाहिए (व्यवधान) टी० बी० के जो कीटाणु हैं इन से देश की और समाज की रक्षा की जाए, नहीं तो प्रगति नही होगी।

तीसरी बात की ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि बहुत से विदेशी लोग या बहुत सी विदेशी संस्थाएं हमारे देश में नाना प्रकार का प्रचार और प्रसार करती है और इन संस्थाओं में अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी बहुत सी है और वे हमारी सहायता भी करती हैं, हमारी मदद भी करती हैं। ये वे लोग हैं जो हमारे हितों के विरोधी हैं, सामान्य जनता के हितों के विरोधी और सारे संसार की सामान्य जनता, जो कि सुख शान्ति और चैनपूर्वक रहना चाहती है, के हितों के विरोधी हैं। मै विशेषकर अमरिकन सामाजिक संस्थाओं की बात करना चाहता हूं जिन के माध्यम से हमारी गरीबी, हमारी दरिद्रता का प्रचार और प्रसार किया जाता है। अभी 26 तारीख के 'आज" अखबार में छपा था कि इन्टरनेशनल राटेरी ने कोई हमारा मानचित्र एक पुस्तक में छापा, तो उस मानचित्र में हमारा बहुत बड़ा अंग नही दिखाया गया है। यदि विदेशी माध्यम के प्रचार को और यह जो कोका कोला के विज्ञापन आप देखते है हमारी विजय पर, उनको आप देखे तो वे भारत की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले है भले ही उस में कोई बात साफ ढंग से न लिखी हो। मेरा कहना यह है कि इन संस्थाओं के अंतरंग का पता लगाया जाना चाहिए।

एक बात और कहना चाहता हूं कि प्रिवी पर्स समाप्त कर दिया, राजाओं के विशेषाधिकार हमने समाप्त कर दिये। यह हमने बहुत अच्छा किया और इस को बहुत पहले हो जाना चाहिए था, किन्तु देश की हजारों वर्ष की कलात्मक वस्तुएं और हमारे ज्ञान विज्ञान के ग्रन्थ, इन के संग्रहालयों में पड़े हुए है और कुछ उनका व्यापार भी करते है। बहुत से सड़ जाते है और उनकी व्यवस्था नही कर पाते है। इन को शासन को अपने हाथ में लेना चाहिए। कानून बना कर हमारे ज्ञान, विज्ञान, कला और संस्कृति की चीजें जो कि जनता के हाथों से बनी थी, जनता की गाढ़ी कमाई से जो बनी है, उन के निश्चित रूप से सरक्षण और सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए क्योंकि वह शासन बड़ा होता है, वही लोग बड़े होते हैं, वही सरकार बड़ी होती है, जो कला और संस्कृति को प्रोत्साहन देती है। वास्तव में वह गरीब लोगों की कमाई रही है। राज दरबार में जो साहित्यकार और कलाकार रहते थे, वे अपने पेट के भोजन के लिए और जीवन यापन के लिए अपनी कला को इन राजाओं के मनोरंजन के लिए बेचते रहे और उन का संग्रह उन के पास है, जिस को अगर कोई देखना चाहे, या परखना चाहे तो देख और परख नहीं सकता है। मेरी सरकार से प्रार्थना है, मेरा सरकार से आग्रह है

[श्री सुधाकर पांडे]

कि इन कला-कृतियों को जिन का व्यवसाय बड़े व्यापक पैमाने पर हो रहा है, अमरिका से भी हो रहा है और बहुत तेजी से होता है, उसको रोके । मैं समझता हूं कि लाखों करोड़ों रुपये की चोरबाजारी हो रही है । इस को रोकने के लिए विधेयक तो आने वाला ही है किन्तु वह विधेयक पर्याप्त नहीं होगा । इसलिए मेरा यह कहना है कि इन राजा-महाराजाओं के संग्रहालयों को राष्ट्र की सम्पत्ति घोषित कर दिया जाए और उन्हें निश्चित रूप से सरकार को ले लेना चाहिए ।

अन्त में मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि समाजवाद की यदि स्थापना करनी है, तो वह भारतीय भाषाओं से ही होगी और उसके उन्नयन के लिए कार्य करना होगा । अगर उस के उन्नयन के लिए कार्य नहीं करते हैं और वोट लेने की भाषा को, जन जीवन की भाषा को शासन की भाषा नहीं बनाते हैं तो निश्चित रूप से हम अपने साथ और अपनी जनता के साथ फरेब करते है ।

इन शब्दों के साथ मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण का अभिनन्दन करता हूँ और सरकार से जो मैं ने अनुरोध किया है, मैं विश्वास करता हूँ कि सरकार उस पर अवश्य विचार करेगी ।

श्री प्रताप सिंह नेगी (गढ़वाल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं, राष्ट्रपति महोदय के भाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव है, उस का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ । मुझे इस बात की खुशी है कि हमारी सरकार ने समाजवाद का नारा केवल नारा ही नहीं लगाया है बल्कि समाजवाद को मूर्त रूप देने के लिए कदम भी उठाने शुरू कर दिये हैं और सब से बड़ी बात है कि गरीबी हटाओ, गरीबी मिटाओ, यह आन्दोलन ही नहीं बल्कि इसको कार्य रूप में परिणत करना भी आरम्भ कर दिया है । इसके लिए मैं अपनी सुयोग्य प्रधान मंत्री को जितना भी धन्यवाद दूं वह थोड़ा ही है । मुझे आपके द्वारा यह भी कहने का साहस हो रहा है कि सरकार ने इस समय हमारे पूर्वोत्तर के पहाड़ी प्रान्तों को पूर्ण राज्य का दरजा दे दिया है । जो आज तक बिल्कुल पिछड़े हुए थे । मैं आपके द्वारा यह कहने का भी साहस कर रहा हूं कि पर्वतीय और सीमान्त क्षेत्रों हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल, मेघालय, त्रिपुरा, आदि उनको राज्य का दर्जा दे दिया गया है और उनको यह अवसर प्रदान कर दिया गया है वे अपने पिछड़े हुए इलाके को उन्नत बनाने के लिए स्वयं प्रयत्न करें और अपने पैरों पर खड़े हों । लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ आपके सामने यह कहना पड़ रहा है कि हमारे उत्तर प्रदेश के जो आठ पहाड़ी जिले हैं, वे आज भी बहुत ज्यादा पिछड़े हुए है और उनको कोई देखने वाला नहीं है । मैं आपके द्वारा सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि 1961 में दस-ग्यारह मार्च को इसी दिल्ली में गढ़वाल के सैकड़ों हमारे भूमिहीन भाई एक बड़े भारी जत्थे के साथ प्रदर्शन करने आए थे और उन्हें हमारे स्वर्गीय राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद जी ने आश्वासन दिया कि उत्तर प्रदेश की सरकार को वह लिख रहे है और उनकी भूमि समस्या हल हो जाएगी । लेकिन आपको सुन कर ताज्जुब होगा कि आज ग्यारह वर्ष पूरे हो गए है लेकिन एक चप्पा भर भूमि भी किसी भूमिहीन को आज तक नहीं दी गई । हमारे भूमिहीन भाई कभी जेल मे सड़ते है और कभी वहीं भटकते है लेकिन भूमि उन्हें मुहैया नहीं होती है ।

इसी प्रकार मैं आपको यह भी बता देना चाहता हू कि 1962 की पहली सितम्बर को आज के संचार मंत्री श्री बहुगुणा जी ने कर्मभूमि में लिखा था कि गढ़वाल ही नहीं बल्कि हमारे उत्तर प्रदेश के जो आठ पर्वतीय जिले है वे पूरी तरह से पिछड़े हुए है और अगर उनको जनता को शरणार्थियों की संज्ञा दी जाए तो यह कोई अत्युक्ति नहीं होगी । यह हालत हम लोगों की है । इसके अलावा जून 1966 मे हमारी जनप्रिय प्रधान मंत्री जब पौड़ी में तशरीफ लाई थीं तब उन्होंने एक सार्वजनिक सभा में वहां भाषण किया था और अपने भाषण में उन्होंने कहा था कि मैंने आज तक ऐसी गरीबी के दर्शन नहीं किए जिसको कि मैं गढ़वाल में देख रही हूं ।

यह गरीबी 1947 से पहले जब हम लोग गुलाम थे तब जरूर देखने को मिलती थी लेकिन आजाद होने के बाद मैं पहली बार ऐसी गरीबी देश के किसी भाग मे देख रही हू ।

उपाध्यक्ष महोदय, आप तो जानते ही है कि हमारी सीमा एक तरफ तिब्बत से मिली हुई है और दूसरी तरफ नेपाल से मिली हुई है। वह एक पहाडी इलाका है । वहाँ अन्न का उत्पादन नही के बराबर होता है। इस वास्ते आपको देखना पडेगा कि किस तरह की फल पत्तिया वहा उग सकती है, किस तरह से जडी बूटियो का अच्छा इस्तेमाल हो सकता है, किस तरह से उद्योग वहा चल सकते है और किस तरह से इस इलाके की बहबूदी हम कर सकते है । आबादी के लिहाज से भी जिन पहाडी और सीमान्त इलाको को इस समय स्वायत्तता प्रदान की गई है, जिन को पूरे प्रान्त का दर्जा दिया गया है, उन मे से केवल काश्मीर ही एक ऐसा इलाका है जोकि हम से आबादी में बडा है और वहा की आबादी हमारे पहाडी जिलो की आबादी से आठ लाख अधिक है । बाकी जितने भी इलाके है जिन का मैने जिक्र किया है उनकी आबादी हम से कम है । हमारी आबादी 35 लाख 7 हजार है जबकि हम के बगल मे हिमाचल प्रदेश की आबादी 34 लाख है । इसी तरह से बाकी जितने भी पर्वतीय सरहदी सूबे बने है, उनमे किसी की आबादी पन्द्रह लाख, सोलह लाख से अधिक नही है । हमारी आबादी दूसरे नम्बर पर है इन पहाडी और सरहदी इलाको मे । हमारी प्रधान मंत्री जी गरीबी हटाना चाहती है, गरीबो को राहत पहुचाना चाहती है, बेरोजगारो को रोजगार देना चाहती है । मै समझता हू कि समय आ गया है कि आज हम लोगो को भी अपनी किस्मत का फैसला करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए और इन हमारे आठ पर्वतीय जिलो को स्वायत्तता प्रदान कर दी जाए, हम को भी मौका दिया जाए कि हम हिमाचल प्रदेश की तरह, काश्मीर की तरह, नेफा की तरह तथा दूसरे पर्वतीय प्रान्तों की तरह अपने इलाके की तरक्की के लिए स्कीमे बना सके, अपने इलाके को उन्नत बना सके । हमारी प्रधान मंत्री विशाल हृदया है, उनके दिल मे गरीबो के लिए दर्द है, इसे मिटाने के लिए बेचैन हो उठती है और यदि उन जैसी सहृदयी प्रधान मंत्री जब हमारे पास मौजूद है और वह समाजवाद की ओर बढना चाहती है, उनके होते हुए अगर हमारा उत्थान नही हुआ, हमारी तरक्की नही हुई तो मैं समझता हू कि भविष्य मे कभी नही हो सकेगी और भारतवर्ष के माथे पर यह एक कलंक का टीका लगा रह जाएगा और इन आठ जिलो की 38 लाख के करीब आबादी की बुरी हालत मे कोई सुधार नही हो सकेगा ।

मैं निवेदन करना चाहता हू कि समय आ गया है जब आप हमे मौका दे और मैं आपको बता देना चाहता हू कि हमारे ये पहाडी जिले ऐसे नही है कि इन मे कुछ पैदा ही न हो सकता हो । देहरादून को आप ले ले, गढ़वाल को आप ले ले, अल्मोडा को आप ले ले । वहा सिमेंट— जिससे बनता है उस पत्थर के पहाड के पहाड भरे पडे है और बडे अच्छे सिमेंट के कारखाने वहा स्थापित हो सकते है। हमारे यहा वन सम्पदा का अपार भंडार है और उसका विकास हो सकता है । हमारे यहा चीड के पेड से जो बिरोजा निकलता है, उसका उपयोग नही होता है । बरेली मे उसको ले जाकर टरपेंटाइन फैक्ट्री मे उसका उपयोग किया जाता है। हम लोग फैक्ट्री के लिए तरस रहे है । मै आपको हाल ही का एक उदाहरण देना चाहता हू । मैंने उत्तर प्रदेश की सरकार को एक दरख्वास्त दिलाई कि और कुछ नही तो कम से कम लिखाई के लिए कुछ कोटा ही वह हमारे लिए मुकर्रर कर दे ताकि यह उद्योग वहा खोला जा सके लेकिन उसका जवाब यह मिला कि अभी यह नहीं मिल सकता है, आगे देखा जाएगा । कागज के लिए बडी मात्रा मे कच्चा माल वहाँ उपलब्ध है । वहा उसका अपार भंडार है । जडी बूटियो का अपार भंडार है । उन सब से वहा की जनता को लाभ हो, इसका मौका हमे दिया जाना चाहिऐ । यदि हमको भी अपनी किस्मत का फैसला करने का मौका मिले तो ज्यादा अच्छा होगा ।

[श्री प्रताप सिंह नेगी]

इन शब्दों के साथ मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा गया है, उसका समर्थन करता हूं और उनको बधाई देता हूं ।

SHRI DEVENDRA SATPATHY (Dhenkanal) : I am extremely thankful to you because you have given me a chance to speak today. For the last so many days I have been sitting through in this House expecting my name to be called at any moment. Fortunately, the Deputy-Speaker who is in the Chair called me, and I am very thankful to him for this, because he has been very kind to call me.

I am grateful to the President for the speech that he has delivered I could not hear his speech but I could only read it ; I could not hear it because there was a lot of noise and disturbance in the Central Hall on that day. But in spite of that disturbance, throughout the country it is a matter of satisfaction that a new wave of hope and confidence has spread all over the country. It seems the nation is preparing for a big change, for a brighter future. During the last four or five years, since 1967, almost all the political parties in the country were given a chance either in this State or that to rule. All these parties have been tested by the Indian people and ultimately it was found that they voted for Shrimati Indira Gandhi's party, that is, the Congress. It seems that our nation has become really politically mature. But we have to go a long way. Our President has pointed out in his speech that peace on our borders is still uneasy and vigilance cannot be relaxed. This sentence is very significant because there is always the fear of our being led into facile optimism.

It is said that we are moving towards socialism. Basically socialism is an economic concept. On the economic front, many things are to be done. In the concluding portion of his Address, the President has said :

> "Let the nation heed the summons of greatness, a greatness not of conventional power but of the spirit".

What is that spirit ? We speak of *garibi hatao*.....,

SHRI SHASHI BHUSHAN (South Delhi) : It is *amiri hatao*.

SHRI DEVENDRA SATPATHY : Both are the same thing because unless *amiri* is driven away, *garibi* will not go.

As I said, on the economic front, many things remain to be done. People need a new inspiration to dedicate themselves to hard work. What is this dedication ? We have to transform the present competitive society into a co-operative society. It is a long way to go. It is just like the iron ore fresh from the mine being transformed into steel for being made into a surgeon's knife. The iron has to be put in the furnace, melted, purified, beaten into shape and then made into the surgeon's knife. The same process a nation has to go through when it is undergoing a transformation from a competitive society to a society of co operation. It has to go a very long way encountering much difficulty on the way.

Here the President refers to greatness not of conventional power of the spirit. What is that spirit ? During these anxious days we passed through, a woman of India has shown to the world the way it has to go. I am not just praising Shrimati Indira Gandhi, though, of course, I do ; but it is not like that. All thinking people in this country believe and are confident and sure that this woman of India has shown the way to the world in which way it should go. I think this is the power of the spirit.

Today many nations have the power to destroy the whole world. Sitting in their home places and pressing a button, they can destroy any nation in the world. This is conventional power. But the President is asking us to be great not in conventional power but in the power of the spirit. What is that spirit ? If nations have got the power to destroy the whole world by sitting at their own place and pushing a button and if we have the power in this country, if we can save the world, we can say that we have got the power of the spirit. Fortunately enough, this spirit is not unknown to this country, to this nation. This nation has always been the worshipper of spirit. In the midst of our military, economic and social preoccupations, we need to be deeply aware of the spirit and the soul of our nation, and the power of our soul.

Again, you may ask what is the relation between *Garibi Hatao* and the power of the soul ? If we look deeply into the history of India, we can find that when India was at the zenith of its prosperity, the vibrations of her soul were heard abroad *Garibi Hatao* is not merely a distribution of wealth. Economic prosperity depends on ever-increasing production. To have more production, the people must be enthused, the people must be at their high spirits to work hard, and to work more. Production depends upon the enthusiasm of the people. It depends upon the joy of work. If a person does not get the joy of work, he cannot work. If you go to the villages, you see that when we ask the people to work ; they do not have the joy of work Among the officials, clerks and others, you find that they do not have the joy of work. If the joy of work is not there, you can shout and you can talk and do so many things but you cannot make them work.

SHRI K. MANOHARAN (Madras North) : Why is it not found ? Please tell us.

SHRI DEVENDRA SATPATHY : I will tell you ; I am a bad speaker ; but allow me to say—

SHRI K. MANOHARAN : No ; not that ; please enlighten us.

SHRI DEVENDRA SATPATHY : It is just like this. If you take a cup of water and go on beating it for four days and drink it, it would not taste sweet. But if you can put a spoonful of sugar into it, without beating it for four days, you find the sweetness of water. So, something is lacking in this. That sweetness is lacking here. That is why we are going on beating the water for several days, months and years, but that sugar is lacking. So, what is that sugar ? That is what our President has pointed out. (*Interruption*)

For *Garibi Hatao*, we need also have proper distribution. If we have a dead machinery for distribution, you are a dead nation. If we have a living machinery for distribution, then you are a living nation, when the entire nation pulsates with the living force of soul. That is why we need a good system of education. I am surprised at the President's Address ; I read it very carefully, but I find that the President has been absolutely silent about education. I do not know why he preferred to be silent about education. For the last 25 years, education is a subject that has been utterly neglected, Even now it is neglected. Commissions after Commissions are being set up. Recently, the Kothari Commission was set up and the Kothari Commission said that the aim of education is socialism, secularism and democracy and all that. But what is secularism ? I have asked many people, and they have not been convinced, what is secularism. The Kothari Commission has gone into it in some depth and said that secularism is not inconsistent with spiritual and moral values, and it has recommended that spiritual and moral values should be taught to the pupils. But nothing has been done as yet. Even big people in charge of the Education affairs do not understand what is secularism Recently I had had some discussions with some persons ; they do not know what secularism is They say everything. Why is there a chair for Islamic studies in the university, I ask ? Can they say it is not secular ?

MR. DEPUTY-SPEAKER : You want to lay stress on education. You can do so at great length on the Demands for the *Education Ministry. There are many* persons wanting to speak from your party. Please conclude.

SHRI DEVENDRA SATPATHY : The President's Address remained silent on this matter. That is why I referred to it.

Recently, we say that our country had reached great heights and it had been acclaimed throughout the world that India showed the way. It is not because we captured a large number of soldiers from Pakistan or defeated them in war. It is because we stood for an ideal. We have to stand and work for that ideal. That is why the President has said that we must heed the call of the spirit and mould our actions according to that.

MR. DEPUTY SPEAKER : Shri D. K. Panda. Please do not exceed five minutes.

SHRI D. K. PANDA (Bhanjanagar) : While speaking on the Presidential Address, I would like to state first that the right

[Shri D. K. Panda]

reaction is on the rout and it was due to the mobilising capacity of the people and also the conciousness of the people. People have given a massive mandate to the ruling party. It is now to be seen how far the ruling party is going to respect it.

There is no mention in President's Address about adivasis, who are 10 crores. There is no programme for them. There is no reference to the introduction of a law for agricultural labourers to ensure that they get a minimum wage. There is not even a whisper about the land-to-the tiller slogan.

I welcome the *garibi hatao* slogan. If the Government have understood its concept, they will not treat it as a song or a prayer ; it has to be translated into action, into economic and political terms. It has to be made tangible. For that purpose what has been done for the rural sector ? Your *garibi* cannot be *hataoed* like this. Ten Chief Ministers can be *hataoed*, but to *hatao* a landlord is difficult ; perhaps that is how the Government finds it.

There is an example from Andhra. A rich landlord, who was a Congress MLA, is now the Minister of Religious Endowments, and has managed to evict 500 workers from their lands Though the Sessions Judge has clearly given his judgment in favour of the tenants, no action has been taken so far against the Minister. So, if your Ministers in the States are going to act as agents of the big landlords in the rural areas, if they themselves acquire lands and appropriate lands for their own interests, how can the programme of *garibi hatao* be ever implemented ? Is this the way to respect the massive mandate of the people ?

Similarly, in Orissa 6,000 acres have been taken over by a particular Minister, and 2,000 tenants have been evicted. Similarly, in Bihar one of the Ministers is in possession of 23,000 acres of land. I congratulate friends on the other side like Mr. Shashi Bhushan and others who have taken up these matters. How can land reforms be implemented and poverty removed if Ministers at the State level hold thousands of acres of land ?

I agree that the rural rich should be taxed for mobilising our resources, as they have harvested huge profits from the green revolution.

The question of foreign capital and foreign monopoly collaboration is very important. Our programme of self-reliance cannot be fulfilled by a mere slogan. The President's Address should have given a direction for nationalisation of all the foreign monopoly ventures. Foreigners who have invested only Rs. 15 lakhs have already reaped Rs. 4 crores and still they are allowed to loot and plunder our country As dollar imperialism is in crisis today, make hay while the sun shines. Strike at the foreign monopolists, nationalise the oil companies, the tea gardens and coffee gardens held by them. Then only can our country take to the path of independent economic development. Otherwise, it is not.

15 hrs.

Really I am shocked to learn from the papers that our Prime Minister, addressing the 45th annual conference of the FICCI, spoke about collaboration in the joint sector. In 1948 according to the Industrial Policy Resolution, the policy was curbing monopoly capital. Then came the slogan "regulate and control" after the 20th Amendment. Now, after stability of the Congress has been achieved in each State, you talk of collaboration in joint sector ! Are we to understand the implication of socialism and *gharibi hatao* in this way ? Therefore, my appeal to the Government is, whoever replies tomorrow, the answers to my points should be given. These are welcome slogans, but they have to be concretised.

श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा (नवादा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए सर्वप्रथम अपने प्रधान मंत्री, प्रतिरक्षा मंत्री और सेना के तीनों सेनाध्यक्षों और जवानों को बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने अपनी दूरदर्शिता, सामयिक कदम, दृढ़ संकल्प, बहादुरी और सारे कारनामों से इस राष्ट्र का सिर ऊँचा किया है। मैं इस सदन में माननीय सदस्य श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का भाषण बड़े गौर से सुन रहा था। उन्हें राष्ट्रपति महोदय के भाषण का यह अंश कि महानता इस राष्ट्र का आवाहन कर रही

है खोखला नजर आया तथा देश का लोकतंत्र खतरे में है, ऐसा उन्होंने बताया। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहने की हिमाकत की कि आज प्रधान मंत्री तानाशाह बनती जा रही है। यह सारी बातें हमारे विपक्षी दल के माननीय सदस्यों को उस समय दिखाई पड़ने लगी जब लोकसभा के चुनाव से लेकर सारे देश की विधान सभाओं के चुनावों में उनकी करारी हार हुई। इसके बाद इन्हें सारी चीजें इसी रूप में नजर आने लगी हैं। मैं बड़े विनम्र शब्दों में उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि सबसे पहले आप इस बात पर गौर करें कि आपकी यह बुरी अवस्था क्यों हुई? देश के अन्दर प्रधान मंत्री जी की लोकप्रियता किस आधार पर बढ़ी? तो आप पायेंगे कि लोकसभा के चुनावों में इन सब लोगों का जो सिद्धान्त-विहीन विशाल गठबंधन हुआ जिसमें किसी तरह का कोई कार्यक्रम या सिद्धान्त नहीं था, केवल यही नारा था कि इन्दिरा हटाओ। तो इस सिद्धान्त विहीन गठबंधन तथा गलत नारे के कारण ही इनकी यह बुरी अवस्था हुई है और दूसरी तरफ प्रधान मंत्री का नारा था गरीबी हटाओ तथा कांग्रेस के मूलभूत सिद्धान्तों के आधार पर देश का आवाहन करती थी। यही कारण था कि प्रधान मंत्री की लोकप्रियता बढ़ी। अंत में विपक्षी दल तथा श्री वाजपेयी जी से निवेदन करता हूं कि वे आत्मचिन्तन करें।

उपाध्यक्ष महोदय, हमने भी आत्मचिन्तन किया था सन 1967 के चुनावों के बाद कि इस देश की जनता कांग्रेस से विमुख क्यों हुई तो एक बात हमें नजर आई। जो हमारे मूलभूत सिद्धांत थे, जो हमारे कार्यक्रम थे उनको वास्तव में जमीन पर उतारने की हमने चेष्टा नहीं की इसीलिए जनता में रोष आया। उस चिंतन के प्रभाव के कारण ही देश में कांग्रेस का विभाजन हुआ, श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का एक विशाल संगठन बना और उन सारे मूल-भूत सिद्धांतों और कार्यक्रमों के लिए आवाज उठाई गई और श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व पर देश की जनता को भरोसा हुआ। कांग्रेस संगठन में पहले जो कुछ ऐसे तत्व थे जोकि समाजवादी कार्यक्रमों का विरोध करते थे, उन कार्यक्रमों को जमीन पर उतारने और लागू करने का विरोध करते थे, वे सारे तत्व संगठन से बाहर चले गये और जो लोग रहे उनका सफल नेतृत्व प्रधान मन्त्री जी ने किया और जनता ने भी उनके नेतृत्व पर भरोसा किया। आज उसी का परिणाम है कि लोकसभा के चुनावों से लेकर सारे देश की विधान सभाओं के चुनावों में कांग्रेस को प्रबल बहुमत मिला है। दूसरी ओर जो सिद्धान्त विहीन विशाल गठबंधन बना था उसने सारी चीजों को एक गलत तरीके से देश के सामने रखा और उसी के परिणामस्वरूप विपक्षी दलों की यह अवस्था हुई है। इन बातों पर विचार न करके विपक्षी दल एक प्रचार का यन्त्र बनाकर कह रहे हैं कि लोकतन्त्र खतरे में है और प्रधान मंत्री तानाशाह बनती जा रही है। इन लोगों ने बड़ा शोर मचाया इस बात का कि विगत युद्ध का श्रेय प्रधान मंत्री लेना चाहती है। मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री ने कभी इस बात की चेष्टा नहीं की कि युद्ध का जो श्रेय है वह उनको मिलना चाहिए। विपक्षी दलों ने देश में बड़े जोर शोर के साथ इस बात का आन्दोलन किया कि प्रधान मंत्री को इसका श्रेय नहीं मिलना चाहिए लेकिन श्रेय देने का काम मेरा और आपका नहीं है बल्कि यह काम देश की जनता का है। जनता ने समझा है कि युद्ध का श्रेय किसको है। आपके सारे प्रचार के बावजूद देश की जनता ने अपनी लोक प्रिय नेता प्रधान मंत्री के वाजिब कदमों को समझा और उसका श्रेय प्रधान मंत्री को दिया या नहीं लेकिन इतना तो जरूर हुआ कि जनता ने उनके कामों को देखकर उन पर भरोसा किया और अपना प्रबल समर्थन प्रदान किया। आज केवल देश में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी हमारी प्रधान मंत्री एक उद्धारक के रूप में देखी जाने लगी हैं। इस दृष्टिकोण से आपके प्रचार के बावजूद इसका सारा श्रेय प्रधान मंत्री जी को ही मिला है।

ऐसी हालत में मैं समझता हूं विपक्षी दलों को अपने इस प्रकार के सारे प्रचार बन्द करके,

[श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा]

अपनी नीति और अपने कार्यक्रम को ही सही ढंग से जनता के सामने और देश के सामने रखने चाहिए। आज देश में जो जनतंत्र को पनपाने वाली चीजें है, गरीबी और बेकारी को हटाने के लिए जो कार्यक्रम चलाए गए है इसमे ईमानदारी का तकाजा है कि यदि आप वास्तव में इस देश में जनतंत्र के प्रेमी है और देश में समाजवाद लाना चाहते है तो डटकर इन कार्यक्रमों का समर्थन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा मार्ग आपके लिए हो नही सकता है।

अन्त में मै आपका ध्यान गरीबी बेकारी हटाने के नारे की तरफ तथा अपने पिछडे प्रदेश बिहार की ओर ले जाना चाहता हू। बिहार मे प्रचुर मात्रा मे प्राकृतिक सम्पदा विद्यमान है, वहा की धरती उपजाऊ है वहां के लोग परिश्रमी है परन्तु बावजूद इन बातो के जहा पहले बिहार का स्थान देश मे पर कैपिटा इनकम के हिसाब से दसवां होता था अब 16वां स्थान हो गया है। यह बड़े दुख की बात है। मैं सरकार से तथा प्रधान मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि राष्ट्र सबल तभी हो सकता है जबकि पिछड़े इलाकों को समृद्ध बनाया जाये। पिछड़े हुए इलाको की तरफ केन्द्रीय सरकार का ध्यान जाना चाहिए। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि बिहार आज क्यों पिछड़ा हुआ है उसके कारण है। नौकर-शाही का बोल-बाला। सारा प्रशासनिक यंत्र बिहार की जातीयता एवं दलबन्दी मे पटा हुआ है और समाजवाद तथा गरीबी एवं बेकारी हटाओ कार्यक्रम के प्रतिकूल विचार रखने वाला है तथा उनका आचरण है। बराबर मंत्रीमण्डलो का गठन भी जातीयता एवं दलबन्दी के आधार पर ही होता रहा है। यही कारण है कि आज सारे साधनों के बावजूद भी बिहार पिछड़ा हुआ है। जैसा कि हमारे माननीय मित्रों ने कहा कि आज का जो प्रशासनिक यंत्र है चाहे वह केन्द्र का हो, चाहे वह बिहार का हो और चाहे दूसरे राज्यों का हो वह इतना निकम्मा है तथा समाजवाद का विरोधी है कि जो समाजवाद को आगे बढ़ने नही देना चाहता।

उपाध्यक्ष महोदय, वह प्रशासकीय तंत्र आज सचमुच में इतना निकम्मा हो गया है कि देश के समाजवादी जो कार्यक्रम है उनको आगे बढ़ाने में असमर्थ पा रहा है और उसमें बाधा पहुंचा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, इन बातों के साथ मैं आप से एक निवेदन और करना चाहता हू कि हमारे बिहार के अन्दर जो प्रशासनिक तंत्र है वह जातीयता और दलबन्दी के चंगुल मे फसा हुआ है। उसकी तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। साथ ही साथ मैं अपने क्षेत्र की तरफ आप का ध्यान दिलाना चाहता हू।

MR. DEPUTY-SPEAKER : There are many speakers from your party. Please try to conclude now.

श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा : मै सिर्फ दो मिनट ही लूगा। मैं अपने क्षेत्र की तरफ आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

MR DEPUTY-SPEAKER . This should be mentioned in the Bihar Legislative Assembly and not here. Please try to conclude now.

श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, जब भी मौका मिलता है, तभी कहता हू। मैं जिस प्रदेश से आता हू उस मे मेरा गया जिला भी है (व्यवधान) वह औद्योगिक विकास मे बहुत पिछड़ा हुआ है। वहां एक कोटन और जूट मिल थी और दो चीनी की मिले थी जो काफी समय से बन्द पड़ी हुई और वहां पर हजारो मजदूर बेकार पड़े हुए है यथाशीघ्र चालू करानी चाहिए। (व्यवधान)···इसी तरह से खेती के सम्बन्ध में भी है। मेरा कहना यह है कि गया जिला की जमीन उपजाऊ है। लेकिन सिचाई के अभाव मे फसल मारी जा रही है। सारा जिला बराबर अकाल का सामना कर रहा है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में अपर सकरी रिजर्वायर, मोहान रिजर्वायर तथा दि डाइवर्जन स्कीम और पुन पुन नदी तथा कोपना डाम स्कीम को लेकर पूरा करने की अति आवश्यकता है। सरकार से यह

मेरी जोरदार शब्दों में मांग है। इन योजनाओं के बन जाने से सारा गया जिला अन्न के मामले में सिर्फ स्वावलम्बी ही न होगा बल्कि लाखों टन अनाज बाहर भेजने मे समर्थ होगा। इन शब्दों के साथ मैं धन्यवाद प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। (व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER : Order, Order ; Shri Syamnandan Mishra.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA (Begusarai) : Mr. Deputy-Speaker, Sir, one feels extremely sad to note that the gracious Address of the esteemed President does not make any mention of the basic fact of the Indian situation today that the nation is on a declining curve both materially and morally, if I can use the word 'morality' in the sense of political morality, values, norms and standards. If we do not see this fundamental fact of the situation "with the hottest fire of our sight" or, as the political scientist would like to say, if we lose "the threshold of perception" to foresee the all-pervasive disaster that might come sooner than later, it would really prove disastrous for the country Maybe, we are all responsible to some extent, in some measure, for this kind of situation that is developing, but we have no doub that every reasonable man would say that the Government has to bear the cross largely for it.

When I spoke about the nation being on the declining curve materially, what exactly did I mean ?

On the material plane you find that our country's position in the GNP (Gross National Product) map of the world has been deteriorating. A few years back our ranking was the seventh in the world, but now it has gone down to the eighth. The seventh ranking was in the Year of Grace 1965. After that the new regime begins.

It relation to our main rival, China, we have been slipping fast, so fast indeed, both in economy and defence, that nobody considers us to be in the race at all with that country.

China began almost with the same quantity of production of steel in the year 1949. Now it has gone upto 20 million tonnes. But where are we ? We are trailing behind in a slow coach at 1/3rd production.

Similarly, in the matter of petroleum, China has become nearly self-sufficient, whereas we are not able to meet even 1/3rd of our national requirement.

In the field of defence, it is well known that China is now considered to be one of the super powers with its atomic arsenal growing fast and its missile development also taking place at a very rapid pace. China, as you know, is already the third submarine power in the world.

At this rate, we might very well reconcile ourselves to being within the sphere of influence of the Chinese almost like a ryot to a zamindar. To constitute a defence system with some super power and even Bangladesh as a part of it, as some persons would like to suggest, is no viable defence that any honourable country would like to have.

On the domestic economic front, the position is no better. The industrial production has been hovering round the zero rate of growth. The rate of growth in the organised industrial sector is only about 2 per cent, the lowest since Independence. I would not concede the figure that is being bandied about – that it is somewhere between 3 and 4 per cent.

The problem of unemployment is now becoming explosive. During the last year alone, it has worsened and gone up by 24 per cent. Earlier, the rate of increase in unemployment has not gone beyond 7 per cent year. But during the last one year, it has gone up by more than 24 per cent –another thing which has not been rivalled since Independence. The poor man's rupee has been depreciating at the rate of 10 per cent annually. The poverty of the masses during the last year of the *garibi hatao* programme must have become oppressive indeed if you take into account the price of sugar, salt, oil and other necessities of life. But the Prime Minister finds the faces of children in the rural areas chubbier, brighter, and their cheeks rosier. I think, all these are in the eyes of the beholder. One thought that the mother's eyes would be a little more compassionate.

The disparities, that is, the polarities between poverty and affluence have been increa-

[Shri Shyamnandan Mishra]

sing. The big business and monopoly houses possibly got more licences during the course of the last two or three years than during the last 10 years. They got about 300 or so licences during the last three year—a quarter or more out of the total of 1160 licences, that is 30 per cent of the total share. A very modest share indeed ! One does not know what the Monopolies Commission has been doing. Where is the Monopolies Commission ? Probably, Parliament of India will have to file a report with the police to find out the whereabouts of the Monopolies Commission.

Yet the number of seats bagged by the ruling party has been increasing by leaps and bounds. It seems the masses have a unilateral affairs with the ruling party because, on the one side, unemployment is increasing, prices are rising, and, on the other side, the seats bagged by the ruling party have been increasing by leaps and bounds

Now, on the moral plane—or say it cultural in a broader sense—this Government seems to be hell-bent on having as its epitaph the motto : 'End, not means. (just a revolution in the ethics of politics) corpus not character'. That seems to be the motto, and that seems to be the desire of this Government to have as its epitaph.

Now, it has been said that in a living period, mankind accumulates upwards but in disintegrating period, it accumulates downwards, down to the lowest issue.

The Government has, indeed, inaugurated an era of cumulation downwards, and as surely as the physical law, I have no manner of doubt in my mind the moral law will operate to wreak vengeance on all of us.

Let me first begin. while I am on this moral plane, with what the morning newspapers have been saying to us every day. They have been saying to us everyday on behalf of the State Governments, "Good morning, Ladies and Gentlemen, here is a bottle of whisky for you." Now, that is what the newspapers every morning announce to us and even this morning, on behalf of the Maharashtra Government, a very good gift has been given to us. And all this in a country where we have as the Directive Principle of State Policy !

SHRI K. MANOHARAN : Do you mean to say that drinking is immoral ?

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA : Not immoral But I am not accustomed to that kind of morality.. (*Interruptions*) So, Mr. Deputy Speaker, they have assiduously a climate of social approbation for a contrary policy. Perhaps, this is a new form of '*Garibi Hatao*' programme, because this is their message to the poor people : 'You drown your miserly in a cup of liquor.' There was the Mahatma who gave us one kind of programme for '*Garibi Hatao*', but we have now got this Government which gives us another kind of *Garibi Hatao*' programme Since '*Garibi*' cannot be '*hataoed*', it must be drowned in a cup of liquor'.

SHRI G. VISWANATHAN (Wandiwash) : To be dissolved in a cup of liquor.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA Let it be dissolved.

No wonder, therefore, we find to-day a rising tide of liquor and narcotic drugs inundating almost every nook and corner of this country. Liquor and liquid black money—they are indeed working a havoc on our national character and very soon, this country, would be full of political and social hippies, worse than the hippies whom you confront from outside ..(*Interruptions*). This is not a matter to feel amused amount, for after four or five years, not in the distant future, you will find the country full of such hippies, and this hippism would flourish on the basis of povetry and unemployment, whereas the other happism has flourished on the basis of affluence and property.

Secondly, you cannot fail to take notice of the fact that the Government and the ruling party have openly and actively engineered defections through all manner of seductive devices and corrupting influences which they possess and press into service as Almighty Government.

Thirdly, this Government shields corrupt men in their party occupying high places.

Two or three memoranda were submitted to the President of the Republic by the Mem-

bers of the Legislature of Haryana. This was backed later by 121 Members of Parliament. The Memoranda gave concrete instances of how colossal swindle of Government money has taken place, how things have been purchased at a rate much higher than that prevailing in the market. All these details were given. But the President has not thought it fit to appoint a Commission of Inquiry into the conduct of the Chief Minister of Haryana. On the other hand, when only one person submitted a Memorandum against the Akali Ministry, a Commission of Inquiry was appointed with great despatch and expedition This shows the double standards that the Government practices one for its own partymen and the other for its opponents.

Let me come to the fifth point, when I am on this topic of the moral plane.

SHRI K. MANOHARAN : Come to political plane.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA : The Government has pursued a deliberate policy of creating and augumenting black money so that they may be able to draw freely upon it for their political ends and purposes. Never has politics been so completely under the influence of black money as it is today. In fact, much of the political stability that is being so chirpingly flaunted by hon'ble members on the other side is the result of some Rs. 30 crores collected by the ruling party from the big business and the monopoly houses and so generously used during the elections. Now, it is not out of any socilist fervour or charity that the capitalists have heaped so much of resources on the ruling party. It is on the basis of a *quid pro quo* and a plain business deal. Why was particular business house given so much of money by way of compensation when there was a Bill on the anvil to substitute the word 'amount', for the word 'Compensation' ? Rs. 55 lakhs were given. Why were certain cases dropped against certain business houses quite recently ?

AN HON. MEMBER : They are found unsustainable.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA : That gives the clue ; when the money is yielded the case becomes unsustainable. And, why was no action taken on Vivian Bose Commission's report ? Why was this Vivian Bose Inquiry Commission instituted ? Why has no action been taken, or if any action is being taken, why is the House not taken into confidence ?

AN HON. MEMBER : Action was taken.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA : How have 42 offences of industries which exceeded the capacity been condoned ? One of the offences relates to the venerable beer industry, indeed so socially necessary for the country ! Legal capacity was exceeded by that industry, too !

SHRI K. MANOHARAN : What is the significance of the adjective 'venerable' ?

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA : 'Venerable' because I find myself with you at the moment.

The abnormal rise in the price of sugar and other essential commodities is also the Govornment's way of augmenting black money in the hands of the capitalists, so that they may be able to get a good share out of it.

SHRI M. RAM GOPAL REDDY (Nizamabad) : There are co-operatives also.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA : These co-operatives also might be used in his wonderful State, Andhra Pradesh.

The ruling party has also been collecting money by misusing purchases of public enterprises and through donation *via* advertisements. We are said to be opposed to the United States of America at the present moment, but the Firestone Co. of the United States has yielded not less than Rs. 85 lakhs *via* advertisements. The CEAT has yielded Rs. 25 lhkhs.....

PROF. MADHU DANDAVATE (Rajapur) : Some advertismenets without souvenir.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA : There instances could be multiplied. Everybody knows in this city of Delhi and even outside that some ministers have been taking money not with hands but with buckets and yet you see that they seem to be prospering politically very much.

[Shri Shyamnandan Mishra]

You destroy the character of the country and yet you claim that you are building the country and the nation. One tycoon has been seen moving with bags of money from one house to another and he belongs to the city of Calcutta.

The Prime Minister, at the recent FICCI conference made a speech which shows which way the wind is blowing. It is, indeed, a very interesting speech. She spoke of a chapter of "cheerful co-operation" opening out between the Government and the industrialists. In fact, if I may say so, this chapter of "cheerful co-operation" has not begun now, nor is it going to begin in the future. It had already begun during the period of the two elections, and this is only a *de jure* recognition of a *de facto* situation. But there was another thing about which the Prime Minister spoke and we would heartily agree with that. She said to the industrialists ; "Look here, we have got only three or four years' time ; had we had enough time, the matter would have been different." In fact, she reminded us of what a metaphysical poet, Endrew Marvell said to the coy mistress, namely :

"Had we but World enough and Time,
This coyness, Lady were no crime."

Of course, the big-business requires to be told on this line, and so also this Government.

It is, therefore, not without significance that the slogan of socialism has been scrubbed off the slate, and now you find that the old slogan of self-reliance with a new gloss of "Arthik Swaraj" and with a new glow of satisfaction has been placed before the country. But as H. G. Wells used to say, "You can throw socialism out of the window, but you will come in and find it astraddle your hearth." The same is going to happen here.

Now, is there any newness or freshness about this slogan of self-reliance ? This has been one of the main planks of Indian planning since its inception. This was the programme placed before the country by our great leader Pandit Jawaharlal Nehru, and if we have faced up to the pressures of a foreign countries, it is because of the inherent strength of the Indian economy built under the active guidance and leadership of Pandit Jawaharlal Nehru.

What has this Government done to strengthen the base of one self-reliance ? We hardly find anything to your credit.

I am still on this subject, which might be irritating to my hon friends on the other side —the process of debasement of the national character that has been set in motion.

Now you find that there have been definite allegations that elections had been rigged systematically through the misuse of government machinery under the direct inspiration and guidance of the Central Government.

SHRI K. MANOHARAN : It is a serious charge he is making. Can he prove it ?

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA : Appoint a commission of inquiry. If the Government is not prepared to do that, even the Opposition parties can constitute a committee to go into this matter.

श्री विभूति मिश्र (मोतीहारी) : उपाध्यक्ष महोदय, एसेम्बली कांस्टीट्युएन्सी नम्बर 20 हरसिद्धि में इन के उम्मीदवार ने जो वोट प्राप्त किये है, पहले उनकी जांच की जाये कि उनमें से कितने जायज हैं, कितने बोगस है और कितने लाठी-डंडे के जोर से लिए गये है । यह अपने आप को देवता साबित करते हैं । इनके जो कैंडीडेट जीते हैं, पहले उनके बारे में बतायें ।

AN HON. MEMBER : He has been asked to interrupt.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA : This does not disturb me at all. The way in which the Government have conducted the elections.

**

MR. DEPUTY-SPEAKER : I think this is unfortunate. He should not make such remarks.

AN HON. MEMBER : It should be expunged.

**Expunged as ordered by the Chair.

SHRI SAYAMNANDAN MISHRA : I want it to be on record.

MR. DEPUTY-SPEAKER : He should withdraw those words. He should not speak in such terms.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA : I want it to be on record.

MR DEPUTY-SPEAKER : No, it will not go on record.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA : You can expunge it

SHRI JYOTIRMOY BOSU (Diamond Harbour) : There are definite provisions in the rules governing expunctions.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA : How can you take away the instances I am going to cite for the record ?

SHRI JYOTIRMOY BOSU . You cannot expunge observations arbitrarily.

MR. DEPUTY-SPEAKER : It is unparliamentary and undignified. It is undignified to use that kind of expression about a body that is autonomous and is in charge of one of the most important functions of our democracy.

SHRI JYOTIRMOY BOSU : He has a right to level charges against any body that functions within the country,

MR. DEPUTY-SPEAKER : But it should be in language that is not unparliamentary, that is not undignified.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA : All right. I may also say** But you can expunge it.

SHRI K. N. TIWARY (Bettiah) : He is casting an aspersion on the Chair.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The remarks he made against the Chair will also be expunged.

SHRI SAMAR GUHA (Contai) : On a point of order. This is for our clarification and future benefit Is it wrong to make any criticism of any institution functioning within the country ? I suppose it is permissible to do so.

MR. DEPUTY-SPEAKER : It is not wrong. I am only objecting to the word which I think is undignified, unparliamentary and unbecoming of this House.

SHRI JYOTIRMOY BOSU : To say that the Election Commission has been pressurised by the Government is not wrong...

MR. DEPUTY-SPEAKER : He can use the word 'pressurised'. That is not unparliamentary But that has not been used.

SHRI JYOTIRMOY BOSU : It is a body functioning in this country, and this Parliament has every right to express its opinion the functioning of that body, and you cannot arbitrarily expunge it because he made mention of it, and you cannot shut him cut like that. I say that you are not being fair to us (*Interruption*).

SHRI VIKRAM MAHAJAN (Kangra) : Sir, a point of order.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Leave it to me, Mr. Mahajan. There is no point of order. The matter ends there. (*Interruption*).

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA : My time has been taken up by all these interruptions So, Mr. Deputy-Speaker, all this would show.**

AN HON. MEMBER : Again he uses that word.

SHRI VIKRAM MAHAJAN : Sir, just give me one second I can quote the rule which debars a Member from using these words. These words cannot be used. Neither of these words can be used. For a second, kindly listen to me, for a change Rule 352 (5) of the *Rules of Procedure and Conduct of Business*. of the Lok Sabha says that a Member, while speaking, shall not

> "reflect upon the conduct of persons in high authority unless the discussion is based on a substantive motion drawn in proper terms ;"

** Expunged as ordered by the Chair.

[Shri Vikram Mahajan]

The rule is clear. He cannot, in the debated on the Motion of Thanks for the President's Address, cast any aspersion on any such authority.

SHRI K. MANOHARAN : Is it enacted in the Constitution like that ?

SHRI VIKRAM MAHAJAN : It is in the rules relating to the Lok Sabha There is one more rule which I want to state. It is rule 356, which says :

> "The Speaker, after having called the attention of the House to the conduct of a member who persists in irrelevance or in tedious repetition".

MR. DEPUTY SPEAKER : Order, order There is no question of irrelevance (*Interruption*).

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA : I leave it to the Chair's Judgment. Now, Mr Deputy-Speaker, I have no manner of doubt with whatever facts have been made available to us that the Government has launched upon a course of the most appalling brutality against the child of democracy. In Bihar, in order to concede a genuine victory to them, we will have to confess to complete blindness, deafness and paralysis of all our senses. Whatever we saw, heard or found as realities in the factual situation has been completely falsified by the results and what has come out of the ballot-box. What is the mysterious force working ? In Bihar, there is a saying that the Opposition parties have been defeated by polling before 7 a.m. and polling after 5 p.m. When I speak of the Opposition parties, I do not speak of those parties which have come to the legislatures in Mrs Gandhi's knapsack. I am only speaking of the genuine opposition ...(*Interruption*).

AN HON. MEMBER : Guilty Conscience.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA : We have also no doubt that the Governor of Bihar. **

MR. DEPUTY-SPEAKER : I think that is also not correct, I will tell you that this is against the rules.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA : How ? (*Interruption*).

MR. DEPUTY-SPEAKER : I am reading out rule 352(v) which says that "A member while speaking shall not reflect upon the conduct of persons in high authority unless the discussion is based on a substantive motion drawn in proper terms." If you want to criticise about the behaviour of the Governor, you should bring a substantive motion.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA : The President has been pleased to refer to the elections and it was during the President's rule that the elections were conducted. I will have to say something on the conduct of the elections and the persons who were responsible for the conduct of these elections.

MR DEPUTY-SPEAKER : You cannot cast aspersions on the President. (*Interruption*) I cannot allow it It is against the rules.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA . This is simply unfair ; this is not impartial

MR. DEPUTY-SPEAKER : I am just pointing out the rules. You can bring a substantive motion.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA : You will have to satisfy me why it is not being allowed In fact, I was going to point out that of the Governor. **

MR DEPUTY-SPEAKER : That also will stand expunged. You have to bring a substantive motion.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA : Reference has been made to elections in the President's Address.

SHRI SAMAR GUHA : Is it not a fact that elections were held in Bihar under the President's rule and the Governor is wholly responsible for whatever happens there, for the peaceful and proper conduct of elections ? If the President has in his speech mentioned about elections, how can you avoid a reference to elections in a particular State which was under the President's rule and how can you avoid a reference to the Governor there ?

**Expunged as ordered by the Chair.

MR. DEPUTY-SPEAKER : In the first place it is not the Governor who is reponsible for the elections.....(*Interruptions*) It is the Election Commission that is responsible for the elections..... (*Interruptions.*) All I am saying is that the Governor holds a certain position under the Constitution. If you want to criticise him, you can bring in a substantive motion.

SHRI JYOTIRMOY BOSU : I do not want to cast any aspersion on you. But what has happened to you today ? You are trying to shut him out. We shall be pained in future when we shall have to point out that every utterance which comes from that side does not fit in with the rules. I must tell you that we shall give back those rules with a lot of interest.

MR. DEPUTY-SPEAKER : If it is under the rules, you have perfect freedom. I am not going to stand in your way.

SHRI K. MANOHARAN : You can discipline any Member of this House, but you cannot narrow down the frontiers of his expression..... ...

MR. DEPUTY-SPEAKER : I am not. He is perfectly at liberty to criticise the elections or the way they had been conducted. I am only saying that when he says that the Governor has not behaved in a particular way, I have to point out the rules and say that it cannot be done under the rules.

SHRI SAMAR GUHA : On a point of order. Is it not a fact that elections were held under President's Rule in India ? Is it not a fact that protection of the booth and other arrangements for the smooth and fair conduct of elections are to be made by the police ? Who is responsible ultimately for all these things ? The Governor himself. He is the Principal Administrator under the President's rule. There was a charge of booths being captured in many parts of Bihar. It means that the police were either inactive or it was done with their connivance. Under whose control comes the police administration ? How can one avoid referring to the President ?

MR. DEPUTY-SPEAKER : I am not saying that all these charges have been made from this side and from that side. If you want to criticise the Governor on account of this, you have got to bring a substantive motion.

SHRI JYOTIRMOY BOSU : I do not want to say anything against the Chair, because that will mean casting an aspersion on the Chair, but I am surprised to see that you are not aware of the fact that the upkeep of law and order in the conduct of elections, so far as the physical side is concerned, is naturally in the hands of the State civil administration, and in a State which is under President's rule, the Governor is the principal executive in that regard. So, what else could he say if he wanted to talk about rigging and fraud in elections ? He has to say that the Governor had sided with the ruling party to commit that fraud and rigging.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I have given my ruling. (*Interruption*)

SHRI JYOTIRMOY BOSU : Let your ruling not be as bad as the Governor's action

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA : You can very well, then, permit me to speak about the achivements of the Governor. With deference to you, I would now like to refer to some of the remarkable achievements of the Governor during President's rule in respect of the conduct of the elections.

The Inspector General of Police was transferred four or five days before the by-election to the Lok Sabha was held in Darbhanga. And this was indeed in the interest of law and order and fairness of elections ! A DIG of Police was suspended because he took action against some of the workers of a political party ; probably he still stands suspended. And the wonderful reason given was that he had not vacated the Government premises !

At Madhuban in Champaran District, from which my respected friend Shri Bibhuti Mishra comes, a presiding officer was found stamping ballot papers at the dead of night by a home guard who shot him (Presiding officer) dead.

श्री बिभूति मिश्र : उपाध्यक्ष जी इनको इलैक्शन का पता नहीं है। पहले से कुछ बैलेट-

[श्री विभूति मिश्र]

पेपर को छाप कर रखते है ताकि जब इलैक्शन शुरू होता है तो तुरत-तुरत देते जाते है, वही कार्यवाही वहां हो रही थी जिस समय कि उसने गोली से मार दिया। वह पागल था या क्या बात थी, मुझे पता नहीं, लेकिन श्यामनन्दन बाबू को पता नही है कि इलैक्शन का काम कैसे होता है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : ठीक है, वह हम को पता नही है, हम तो सिर्फ आपके सामने निवेदन कर रहे है।

And you know some of the stories that have appeared in the Bengal press about the way in which elections were held in the State of Bengal. In one constituency called Kamarhatti, 16,000 ballot papers were double-stamped before the counting officer since all others were driven out, and the result was completely different.

The Election Commission has provided this time four ballot boxes per booth Earlier the ballot boxes provided per booth were only two One would like to know the reasons for providing more ballot boxes when the number of voters per booth has gone down. And what are the rules with regard to the placement of these ballot boxes? When would the second box be placed? In fact, this question arises because in one of the constituencies of Bihar it was found that the first ballot box contained only 50 ballot papers, while the second was overflowing with 500 or so ballot papers. These are some of the things which one would like to know about the conduct of the elections.

SHRI K MANOHARAN : How did it happen?

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA : That is something which I cannot say.

We say we have got stability and we all seem to be very happy about it. But may I say that parliamentary stability does not equal political stability? The political superstructure that has been raised is on a very weak economic foundation – in fact, on the foundation of an economy which is eroding fast every day. Just think of what happened in Ceylon. There also the Government had a massive mandate. But only after 10 months or so there was such an explosion in Ceylon that the Government of Ceylon alone could not control it and four or five foreign Governments had to go to the aid and rescue of the Government of Ceylon How was that situation brought about in Ceylon? There were only 650,000 unemployed and the number of educated unemployed was only 14,000. In our country, the number of unemployed is more than 3 crores and the number of educated unemployed is more than 2 million. So, we are indeed sitting on a volcano, about which the Prime Minister spoke during the course of her foreign tour sometime back.

We find in this country socialism has been made unsocialist and democracy has been made undemocratic, the way in which elections have been conducted

What is the answer to this situation? It is our clear conviction that this kind of situation can be met only by mass action on the basis of satyagraha and we will have to think of something on that line Otherwise, the situation is now on the downward slope and it would be difficult for us to control it Let us speak about these facts, before the facts begin speaking themselves and then there would be no time left, it would be too late

We have been currently talking about relations with Pakistan. I will have a word on that. We find that our Foreign Minister has gone to Moscow *via* Kabul We have always heard that on both sides the Prime Minister of India and the President of Pakistan are prepared to have talks unconditionally, without any pre condition. We really do not know what then is coming in the way of such a talk materialising In fact, it would perhaps have been a much better course that instead of our Foreign Minister going to Moscow, we had invited Mr. Bhutto to come over here and have a plain talk with us. Even if we have to go there, we would not lose anything because we should not stand on ceremony when the peace of the subcontinent is involved. We, therefore, want that urgent steps should be taken in that direction.

There is also the question of prisoners of war. I do think our Government views it

only in the political dimension and not also in the human dimension, because the people who are involved are not only combatants but also non-combatants of the order of 5 to 6 lakhs. So, we think some steps should be taken in the direction of solving the problem of POWs on both sides.

SHRI AMRIT NAHATA (Barmer) : Sir, the opposition parties day in and day out raise imaginary ghosts. Yesterday Shri Atal Bihari Vajpayee warned us of what he called the imminent danger of a Tashkent Pact and the possibility of surrender on the part of the Government of India under what they consider Soviet pressure. All these days, we have been told again and again that this government is working under Soviet pressure, when the treaty of friendship was signed with the Soviet Union, we were told that India had comprorised her sovereignty. Later on, when it was proved beyond any doubt that this government, under the leadership of our Prime Minister, defended our sovereignty and security, took decisions independently without and pressures whatsoever, even then the opposition continued to harp on the same refrain that the Government of India was acting under Soviet pressure Only day before yesterday our Foreign Minister made it categorically clear that the decision to declare cease-fire after the surrender of Pak Army in Bangladesh was our own Despite this, my Jansangh friends go on repeating the same old story that the cease-fire was declared under Soviet pressure.

16 hrs.

If we compare the statements made by some responsible American authorities and the statements made by the Jansangh leaders, we find that there is some common link, some common thread between the two. The Jansangh would like us to pursue a policy of which we are being accused by the Americans. After all, these people must have something to say to the electorate. So, they have been raising imaginary fears. But history has always proved them to be wrong. Whether it was the treaty of friendship with the Soviet Union, or the recognition of Bangladesh, or surrender of Pak army in Bangladesh, or the cease-fire, on every count the opposition has been proved to be wrong, and this government took right decisions at right moments The maturity, the far-sightedness and the wisdom of the decisions of the government have always been proved right and the opposition has been proved wrong every time. Today the entire nation, and the people of this country, have full faith and confidence that the best interests of our country, the security of our country, the sovereignty of our country are absolutely safe in the hands of this government This is the experience of our people. People have no faith in the opposition. Jansangh wants to create doubts, but people know that they have been proved wrong in the past ; and they will be proved wrong in the future also.

I would advise my hon. friend, Shri Vajpayee, to take a cue from his American friends Some press people went to Mr. Kissinger and asked him whether the American policy of military assistance to Pakistan was not responsible for India going into the Soviet camp. Mr Kissinger replied "You do not know Madam Prime Minister of India. She is a very determined, cold-blooded woman. She would not go into any camp." Even they recognised that this big country, this great country, led by our determined Prime Minister, would not go to any camp because we jealously guard our independence and sovereignty. I do hope, however, that any decent Indian would object to the adjective used by Mr. Kissinger about the Prime Minister of India, namely, that she is cold-blooded. The Americans, who have been waging the dirtiest war in Vietnam, who have armed Pakistan to the teeth and thereby helped it to massacre three million people in Bangladesh, those cold-blooded Americans have called India's Prime Minister as cold-blooded. If our Prime Minister, who is full of the milk of human kindness, who wants to wipe out tear from every human eye, if she is called cold blooded by Mr. Kissinger, it is nothing but sheer impertinence on the part of Americans. But they also realise that India will not barter her independence and sovereignty to any camp whatsoever.

The Leader of the Cong (O) was just now talking of satyagraha. Having told so many untruths, he spoke of satyagraha. Though these Opposition parties could not arrive at an alliance during these State Assembly Elections, which they forged during the mid-term elections, but the language spoken by them is almost the same. The one new addition or recruitment to their camp is the CPM which during these State Assembly Elections

[Shri Amrit Nahata]

had an objective alliance with the Jana Sangh. In my state, I know it from my experience, at every place the CPM contested the elections in a way that it always helped the Jana Sangh.

They all talk of the elections having been rigged. But when they give examples, they give examples of a consituency here or a constituency there. Shri Mishra was telling about Bihar. But what happened in Rajasthan, Gujrat or Madhya Pradesh ? Do they mean to say that the elections were rigged all over the country ? If they lost constituencies somewhere in some places, they should not generalise from this experience. I am sure, even those concrete instances which they give are totally wrong and baseless.

It always happens that parties which are defeated start finding fault with the election machinery and ultimately with the people. I am sure that ultimately they will find fault with the Indian people. He has already said in so many words that the Indian people are unilaterally in love with the Congress, thereby finding fault with the people themselves. This is the way of all those who have no faith in democracy and in the people of the country.

During these elections to the State Assemblies, I am of the opinion that the people of our country have given not a mandate but a verdict They gave a mandate during the mid-term elections to this House. After one year, when the State Assembly elections were held, the people had an opportunity of giving a verdict and they have given a clearcut verdict in favour of this Government led by Shaimati Indira Gandhi.

There is so much talk about *garibi hatao*. The Indian people and the Indian electorate are mature and wise enough to take decisions. I do not give much credence to the slogan of *garibi hatao*. The Congress never said, *garibi barhao*. *Garibi hatao* is not a new slogan. The Indian people know it very well and have seen it that during the war, during the stresses, strains and crises, the Indian economy has stood the test and has emerged unscathed from the war and the burden of refugees on the economy. The Indian people know that a firm and sound basis has been laid for the Indian economy by the farsighted vision of Pandit Jawaharlal Nehru when he launched planned development in the country. They also know it very well that povetry is a legacy of centuries of backwardness in this country. They know that Shrimati Indira Gandhi does not possess any Alladin's lamp which she would rub and poverty in India would vanish overnight. They know that poverty is there and they have to live with it for years to come. What they resent is not this. There are lakhs of people who sleep on pavements in Bombay. They know that Shrimati Indira Gandhi would not build houses for them within a few months. Lakhs and lakhs of people in our country are homeless today and they know that it will take some time to provide them with homes. But when these pavement-dwellers in Bombay see multi-storeyed scyscrapers rising in Bombay, they resent it.

I want to draw attention to one very important factor. The former Maharaja of Bikaner said that we are talking not of *garibi hatao* but of *amiri hatao*. Social envy and hatred constitute a very potent motive for social tension. Let us recognise this fact. People can live in poverty for years to come but they cannot see the gross injustice that is inherent in the present day sytem. They revolt against this glaring inequality and injustice. When I say that injustice must be removed, it is because I am convinced that justice is a pre-condition even for growth in our economy.

We are told that growth and justice must go together. But I feel that justice is a precondition for growth I will give just one example of land reforms. Do we want land reforms simply because it will mean greater amount of social justice in the countryside ? No, Sir. Our economists and agronomists tell us that with this new farm technology, with the so-called green revolution, the optimum size of a land holding is hardly 3 acres, Beyond that, the land is uneconomic ; beyond that, you will have diminishing returns. So, it is intensive farming which is ideally suited to the new farming technology. Small farm holdings will give us greater production, greater rate of growth in agriculture. That is the conclusion of agronomists also. So, if we have justice in the countryside, if we have a fair distribution of land and equitable distribution of land, it will lead to a greater increase in agricultural produce, not a decrease in it.

Similarly, if we have an element of justice in industrial relations, if we have an element

of justice in distribution system, in trade, then production itself will grow. There will be a greater rate of growth in our economy. That is why I say that even for the attainment of self-reliance, this element of justice is essential.

I want to make it very clear that Indian capital is incapable of contributing anything towards the attainment of self-reliance. Indian capital is hardly capitalistic. It has lost all character of enterprise ; it has lost all character of chartering unchartered areas. It is based on anarchy. I will give you an example. There are so many industries in the private sector. Take, for example, sugar, textiles, soap, drugs and pharmaceuticals. In all these industries where private-sector holds full sway, there is total anarchy, loot and mismanagement. After crores of rupees profit earned by the textile industrialists, there are hundreds of textile mills that are closed down There are thousands of varieties of cloth, of soap, etc. They cannot even say that raw material is not available. There is a glut in cotton ; there is a glut in coconut. The cotton prices have crashed down ; the coconut prices have crashed down. Still the mills are closed. Still the industry is sick. Still there are so many varieties, the cost of transport, the cost of advertisement, nil included, and each variety produced on a small scale costs more and the consumer is swindled. There is total anarchy.

Where is the money they bring from ? Today we are told that strikes must be banned. It is the capital which is on strike, not labour. Where is the capital ? All money that can be invested has gone underground. There is no capital to be invested. If we think that Indian capitalist will bring self-reliance by investing his capital, we are labouring under an illusion. That is why Indian capitalists now is trying and is even reconciling to a position of subordination by inviting foreign capital participation. They are inviting foreign capital. They want to enter and invade even those spheres which have hitherto been reserved for the public sector because, in other spheres of consumer articles, what are called consumer durables or luxury articles, where there is more margin of profit, they have reached a saturation point. There is no demand. There is no market. That is the main reason.

Now, an Indian capitalist manufactures goods which are meant for the consumption of hardly 20 per cent of India's population. About 80 per cent of India's population does not constitute market ; it has no purchasing power. Therefore, firstly, the Indian capitalist has no capital to invest—it is in black money. Secondly, they cannot invest in these industries any more because they have reached a saturation point. That is why they want foreign capital to come into India and enter those spheres which are reserved for the public sector. Thereby, the Indian capital wants to mortgage Indian economy to a foreign capital. This is what we understand by neo colonialism. This will not lead to self-reliance. This will lead to a further foreign stranglehold over our economy. And we shall never attain self-reliance.

Lastly, I want to draw the attention of the Government to one specific problem and since that problem concerns me and my people vitally, I want to focus your attention on that. '*Garibi Hatao*' is a great slogan. '*Anyay Hatao*' is a greater slogan. I want to put one more slogan before this Government. '*Registan Hatao*'. Let me explain this slogan.

16.16 hrs.

[SHRI K. N TIWARI *in the Chair*]

Two-thirds of Rajasthan is desert but it has immense potentialities. There is no water underneath. There is no electricity. There are no roads. Tap that underground water. Give us electricity. Give us fodder. The ratio of man to animal in my place, *viz.* Western Rajasthan is 1 : 6—one man and six animals. Nowhere in the country you will find such immense cattle wealth. Milk is going waste. No buyer for the milk. Milk is more abundant than water, but, there is no buyer. We can have what you might call a 'White Revolution', a 'Milk Revolution'. There is cattle but no fodder. Sometimes, there is fodder but no cattle. There is water, but nobody to exploit it. These paradoxes should be removed. Now, we have a Development Corporation, an autonomous body, for Calcutta development. So also we have Damodar Valley Corporation. Why can't we have a independent statutory authority to develop the Rajasthan desert with all its immense potentialities ? Within five years we can give you planty. We can give you self-reliance. We can rehabilitate five crores of people there in that desert. We can usefully employ them. Cattle, milk, agriculture in all these spheres we can contribute considerably.

[Shri Amrit Nahata]

With small resources and with some imagination and determination let us eliminate this desert first of all.

SHRI S. D SOMASUNDARAM (Thanjavur) : On the 29th March 1972 on the floor of this august House, one of the Members of the House said—I am quoting from his speech :

> "How blind can the Government be to the Indian realities can be seen on the question of Centre-State relations. I must bring to the notice of the House that the slogan raised in Tamil Nadu is not that simple. The slogan is very subtle. They say : Mujibur Rahman fought against Urdu ; we fought against Hindi. Mujibur Rahman demanded provincial autonomy ; we are demanding provincial antonomy. Mujibur Rahman got Bangla Desh ; as to what will happen to us, we leave you to understand.
>
> There is not only a Mujibur Rahman in Tamil Nadu in the person of Shri Karunanidhi ; there is also a Mujibur Rahman in Ceylon in the person of Shri Shelvanayakam. These Mujibur Rahmans are raising their slogan because they know that the Central Government are blind to this question of Centre-State relationship."

Further on, he says :

> "But may I warn you that those people who raise the slogan of Mujibur Rahman inside are not alone ; they are being backed up by forces from outside. Nixon and Chou En-lai met in Peking and discussed the question of Kashmir. When they discussed the question of self-determination for Kashmir, they wanted a diversionary slogan from the south. You are not going to deal with it with arms ? You can deal with an outside power by resort to arms. But you cannot solve this problem with arms."

Sir, I want to say on the floor of this House that what one of the C.P.I. Members said are not real facts. These are misrepresentations, misleading the country and are mis-understandings, connecting Mujibur Rahman and Tamil Nadu with political motivations. The DMK party people are not having less confidence in the integrity and sovereignty of the nation than any others, but we must realise the realities of the situation. The whole country knows that DMK is a party of masses in Tamilnadu. If it is said that Nixon and Chou-en-Lai are behind the diversionary policies in the south, it is insulting to the intelligence of the people of Tamilnadu who have reposed full faith in DMK's nationalist policies.

The CPI cannot exist in India as a political party without the active support of Soviet Russia. We have to realise the reality of the situation. As you know, the Central Government has full control on each and every item. The States have to depend upon the Centre's charity. The Centre has got a whip in its hands in the nature of grants because the grants are given by the Centre at its discretion. Discrition is followed by discrimination Discrimination is developing discontent. Discontent creates agitation. The tendency of agitation affects the harmonious relationship between the Centre and the States. What are the reasons for these ? You know, even before the Independence the Provincial Governments had certain power to collect taxes. But after Independence in 1947, the Constitution of India curtailed those powers of the Provincial Governments. For example, in the 1935 Act the Provincial Government was empowered to collect taxes on the sale or purchase of newspapers and on advertisements published in them, taxes other than stamp duties on transactions in stock exchanges, etc. These were given to the States. But now the States have no power over these items. The major and expanding sources of revenue like the corporation tax, wealth tax, excise duty, customs, export duties, surcharge on income-tax etc. are all in the hands of the Central Government.

The financial aid from the centre to the States may be granted under Article 275 and 282. But financial assistance usually is made under Art. 282, which places the Centre in position of a master dictating terms to the States. I think that it would be better if all financial aid is made on the recommendations of an independent body like the Finance Commission.

Sir, every year the Central Government gives financial assistance to the State Governments in the form of loans which are comparatively more that the grants. As a result of

this loans accumulate into a huge amount. The States are placed in such a position that they are not even able to pay the interests for the loans. In this connection I want to quote the words of the Finance Minister of Tamilnadu, while presenting the Budget for 1970-71 on the 26th February, 1970. He told the Legislative Assembly and I quote him. He said :

> "It is a crucial time for the Central Government to appoint a Federal Debt Commission to look into the entire question with a view to rationalise the pattern of lendings and re-payments."

I would like to say that a Committee of Experts may be appointed for considering the question of loans. In this country, the Prime Minister is controlling the Central Government. She is controlling not only the Central Government but also the High Command of the political party. The High Command is controlling the State units and the elections, and thus the High Command has its hold in the State Assemblies or the State Legislatures and on the Ministers. By this process, the State Governments have become practically administrative units of the Centre. Is it possible for the Centre to keep the States as administrative units in this manner for ever ? The States are, thus discontented with their present role in the Indian federal system and are demanding greater autonomy for themselves. Thus, every time, there is a coflict between the Centre and the States. If the Governments in the Centre and the States are by the same party, then the conflict becomes only a party issue. But when the Governments in the States and the Centre are by different parties, then the conflict becomes a political issue. As you would be aware, the popular Tamil Nadu Chief Minister had requested the Central Government to erect a statue of Raja Raja Chola at Thanjavur, but even this simple demand has been denied by the Central Government.

In this connection, I would like to recall to the House one or two instances which happened during the days of the late Pandit Jawaharlal Nehru. When he was Prime Minister, there was an agitation over the composite State of Maharashtra and Gujarat and there was a demand from Maharashtra and Gujarat for the formation of two separate lingustic provinces. Prime Minister Nehru went there to address a public meeting and called upon the people to suspend the agitation. But he could not even address the public meeting. Ultimately, as we all know, the two linguistic States were formed and the composite State was devided into two States. In the same way, after the agitation by the Andhra people and the sacrifice of his life by Shri Potti Sriramulu, the State of Andhra was formed. In the light of all this, you can see that one cannot keep away the demands of the States for ever.

What else is the alternative before us ? Practically, the Government of India or the federal government is functioning as a unitary government. But I submit that it cannot function as a unitary government for ever. I would suggest that let us all forget our political affiliations and our regional thanking and work together for the independence and integrity of the country. At the same time, I would suggest that we should redraw the entire map of India. Possibly some of my hon. friends may not agree with my views or suggestions, but still I would like to make my suggestions before the House because I love the country more. It is my opinion that the prosperity of the entire country depends upon the prosperity of the federating States and the prosperity of the federating States in turn dependes upon their rich natural resources like rivers and mines and the traditions and culture of the people with the self economical viability of their own. The only, we can set an example to the rest of the world. I would suggest that the entire country should be divided into five big federal States, the first consisting of Kashmir, Himachal Pradesh, Punjab and Haryana, the second consisting of Rajasthan, Maharasthra and Gujarat, the third consisting of Bihar, Assam, West Bengal and Orissa, the fourth consisting of Madhya Pradesh and Uttar Pradesh and the fifth consisting of Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Mysore and Kerala. All these five States could then be formed into a powerful federation. Then only the future of India could be maintained with the requisite sovereignty and integrity. Therefore, I suggest the constitution of a Constituent Assembly to re-write the entire Constitution accordingly. In the meantime, Inter-State Council may be formed according to the existing Constitution under Article 263 with the Prime Minister as Chairman and the Chief Ministers or their representatives as members. The Council must have the power to decide on any question of national importance ; it should also be competent to raise loans, internally and from abroad.

श्री अचल सिंह (आगरा) : सभापति महोदय, मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव का हृदय से समर्थन करता हूं।

राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में बगला देश का जिक्र किया है। बगला देश के बारे में हमारे प्रधान मंत्री ने जो कुछ करके दिखाया है, वह अद्वितीय है। आप को मालूम है कि बगला देश मे पिछले साल 25 मार्च को कत्ले-आम शुरू हुआ और पाकिस्तानी फौज ने वहा के निहत्थे पुरुष, स्त्री और बच्चों को कत्ल किया, उनके घरों को उजाड़ा और लगभग एक लाख लोगो को अपनी जान बचाने के लिए भारत मे आने को मजबूर किया। अप्रैल से अक्तूबर तक करीब अस्सी, नब्बे लाख आदमी, स्त्रिया और बच्चे भारत आ चुके थे। भारत सरकार ने उनका स्वागत किया, उनके रहने, खाने-पीने और चिकित्सा की व्यवस्था की और उनको हर तरह की राहत दी।

इस हालत मे हमारे देश मे बड़ी बेचैनी पैदा हुई कि आखिर यह समस्या कैसे हल होगी। प्रधान मंत्री ने ससार के कई देशो मे अपने नुमायंदे भेजे, ताकि वे बतायें कि पाकिस्तान किस तरह बगला देश में जुल्म कर रहा है और लाखो शरणार्थियों को भारत मे भेज रहा है। जब नवम्बर मे पाकिस्तान की फ़ौजें बार्डर पर आ गईं तो भारत को भी मजबूर होकर अपनी फौजे बार्डर पर भेजनी पड़ीं। जब दोनों देशो की फ़ौजे बार्डर पर आमने-सामने खड़ी थी और ऐसा लगता था कि युद्ध होने वाला है, तो इस खतरे के बावजूद हमारी प्रधान मंत्री यूरोप और अमरीका के दौरे पर गईं। उन्होंने सब देशों की सरकारो, और अमरीका के प्रेजिडेंट, निक्सन साहब, को यहां की हालत से अवगत कराया और कहा कि अगर वे चाहते है कि यह मुसीबत टले, तो वे इस समस्या को निपटाने के लिए दखल दें। किसी ने उनकी बात नहीं सुनी और वह वापिस अपने देश में आ गईं।

उस समय तमाम पार्टिया यह मांग कर रही थीं कि बगला देश को मान्यता दी जाये। लेकिन हमारी सरकार और प्रधान मंत्री को मालूम था कि बगला देश को मान्यता देने का क्या मतलब होता है। बगला देश से जो शरणार्थी यहां आये थे, उनमे से नवयुवको को यहा पर ट्रेनिंग दी गई और वे मुक्ति वाहिनी के रूप मे पाकिस्तान की सेनाओं से लड़ने के लिए बंगला देश गये। जब पाकिस्तान ने 3 दिसम्बर को भारत के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की और भारत पर हवाई हमले किये, तो प्रधान मंत्री ने उसके तुरन्त बाद बंगला देश को मान्यता दे दी। युद्ध से पहले रक्षा मंत्री, श्री जगजीवन राम, ने कहा था कि अगर युद्ध हुआ, तो वह पाकिस्तान की भूमि पर होगा। और वही हुआ। हमारी स्थल सेना, जल सेना और वायु सेना ने बड़ी वीरता के साथ पाकिस्तान का मुकाबला किया और सब मोर्चों पर आगे बढ़ी, जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। इसका नतीजा यह हुआ कि चौदह दिन के बाद युद्ध खत्म हो गया, बगला देश मे एक लाख पाकिस्तानी सैनिको ने हथियार छोड दिये और बगला देश आजाद हो गया। इसके बाद शेख मुजीबुर्रहमान को जेल से रिहा कराया गया और बंगला देश से हमारी सन्धि हुई।

यह एक बहुत बड़ा काम था, जिसको हमारी सरकार और प्रधान मंत्री ने सिद्धान्तों और आदर्शों के आधार पर पूरा किया। यह भी बड़ी हैरत की बात है कि जब यू० एन० ओ० में लड़ाई को बन्द करने के बारे में विचार हो रहा था, तो प्रधान मंत्री ने एक तरफ़ा युद्ध बन्द करने की घोषणा कर दी। इस पर यू० एन० ओ० और संसार की तमाम ताकतें भौचक्की रह गईं। प्रधान मंत्री की इन नीतियों से हमारे देश का गौरव बढ़ा।

पिछले चुनावो में मुख़ालिफ़ पार्टियों ने इस बात की कोशिश की कांग्रेस को हराया जाये, लेकिन दिल्ली सहित तमाम सोलह स्टेट्स में कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी मैजारिटी के साथ कामयाब हुई। इस वक्त तामिलनाडु और उड़ीसा को छोड़ कर सब राज्यों में कांग्रेस सत्तारूढ़ है। चुनावों से पहले श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कहा था कि जनता ने केन्द्र में हमको शक्ति दी है,

अगर वह प्रान्तों में भी हमको बहुमत दे, तो हम अपने समाजवाद के प्रोग्राम को अच्छी तरह से चला सकेंगे। 25 मार्च, 1971 को बंगला देश में जो परिस्थिति पैदा हुई, उसके कारण हमारे विकास का प्रोग्राम रुक गया, क्योंकि हमारी सब शक्ति शरणार्थियों की देखभाल और युद्ध में लग गई। अब सरकार को समाजवाद और ग़रीबी तथा बेकारी दूर करने के कार्यक्रम पर अमल करने का मौका मिला है। लेकिन हमें समझना है कि ग़रीबी हटाना कोई जादू का काम नहीं है। इसमें समय लगेगा। लेकिन हमारी सरकार उस रास्ते पर चल रही है और लोगों को विश्वास है कि वह इसमें ज़रूर सफल होगी। बेकारी को दूर करने के लिए बजट में प्राविज़न किया गया है और ऋण प्रोग्राम बनाया गया है, ताकि अधिक लोगों को काम दिया जा सके।

उत्तर प्रदेश, और ख़ासकर आगरा, बहुत पिछड़ा हुआ है। कमीशन ने रिफ़ाइनरी, तेल-शोधक कारख़ाना, स्थापित करने के लिए आगरा को रीकमेंड किया है। आगरा को पिछले वाइस, तेइस सालों से सैंटर या राज्य सरकार की तरफ़ से कोई इण्डस्ट्री नहीं मिली है। मैं पिछले वर्षों में स्वर्गीय प्रधान मंत्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री से कहता रहा हूं कि आगरा एक इन्टरनेशनल सिटी है। वहां कोई न कोई इण्डस्ट्री लगनी चाहिए। इन्दिरा जी ने मुझे लिखा है कि जिस वक्त हम इस बात पर विचार करेंगे तो हम आगरे को ध्यान में रखेंगे। मेरा यही कहना है कि जो बैकवर्ड स्थान है उनको मौका देना चाहिए ताकि जो वहां कमी है वह पूरी हो सके।

राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में बहुत कुछ कहा है। खास तौर से बेकारी और बेरोज़गारी के बारे में कहा है। उसके ऊपर मैं चाहता हूं कि प्रधान मंत्री और गवर्नमैंट ऑफ इण्डिया ध्यान दें।

एक बात की हमारे यहां कमी है, जो भ्रष्टाचार है और खराबी पैदा हो गई है ऐडमिनिस्ट्रेशन में वह किसी तरह से दूर होनी चाहिए क्योंकि बगैर नैतिकता के कोई भी राष्ट्र तरक्की नहीं कर सकता।

हमारे पब्लिक अंडरटेकिंग के बड़े-बड़े कारखाने हैं। वहां बजाय फायदे के नुकसान हो रहा है खास तौर से लोहा और फर्टिलाइजर में जबकि उनमें अरबों रुपया लगा हुआ है। तो मैंने तो प्रधान मंत्री जी से भी और वित्त मंत्री जी से भी कहा 7 हज़ार करोड़ रुपया इनमें लगा हुआ है, अगर हम दस परसेंट भी मुनाफा करें तो 7 सौ करोड़ रुपया मिल सकता है जबकि आज 300 से 350 करोड़ का घाटा होता है। खास तौर से जो कारपोरेशंस है वह तो बिलकुल इंडिपेंडेंट हैं, उनमें बहुत गड़बड़ी और करप्शन है। मैं चाहूंगा कि उनकी जांच कराई जावे कि क्यों उनमें घाटा होता है। मेरा विश्वास है कि अगर इनकी जांच कराई जावे तो उससे फायदा होगा। मुझे बहुत ख़ुशी है कि जब से श्री कुमार मंगलम साहब आए है उन्होंने इन लोहे के कारखानों की तरफ ध्यान दिया है और आशा है कि वह पैदावार बढ़ाएंगे और उससे देश का फायदा होगा। भिलाई कारखाने की छत गिरने से और भट्ठी टूटने से बहुत नुकसान हुआ है। कारखाना कई महीनों से बन्द पड़ा है। प्रोडक्शन नहीं हो रहा हैं। लाखों रुपये का नुकसान हो रहा है। बेरोज़गारी हटाने और गरीबी हटाने के लिए हमें नये-नये कारखाने खोलने हैं, बैकवर्ड जिलों में काम देना है जिससे लोगों की बेरोज़गारी दूर हो उसमें खास तौर से नैतिकता के ऊपर ध्यान देना है क्योंकि बगैर नैतिकता के कोई भी राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता।

हमने देखा कि दिल्ली में 100 आदमी विषैली शराब पीने से मर गए और अभी 21 और मरे हैं। आज कुछ आदमी शराब की जगह स्पिरिट पी रहे हैं। मैं चाहता हूं कि या तो शराब को रोक दिया जाये या लोग पीये तो उसके लिए अच्छा इन्तजाम हो जिसमें ऐसी घटनाएं न घटें।

मैं राष्ट्रपति जी के भाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव है उसका समर्थन करता हूं और आशा करता हूँ कि जो

[श्री अचल सिंह]

बातें मैंने रखी हैं उनके ऊपर सरकार ध्यान देगी।

SHRI INDER J. MALHOTRA (Jammu) : I rise to support the motion of thanks moved in the House regarding the President's Address As usual this debate has become more of a political and election debate. Only a few minutes back, the leader of the Congress (O) party, Shri Shyamnandan Mishra was analysing the last general election results to the State Assemblies. I have no complaints regarding his analysis of political assessment or his political wisdom. My only complaint is that being the leader of a political party which still claims to have the good of the people as its political and economic goal, he should not doubt the political wisdom of the people of India. A clear verdict was given in the last elections to the various State Assemblies. and this verdict was initially given in the last mid-term poll to the Lok Sabha. This time they reaffirmed their confidence in the leadership of the Prime Minister. After this reaffirmation the responsibility on the leaders who run the Government has become much more. Now I hope that more concentrated effort will be made to implement the programme of socialism initiated in this country.

I would like to say a few words regarding the elections which took place in Jammu and Kashmir. This time nearly 65 per cent of the total voters took part in the elections in the whole of the State. There were only five uncontested seats as against 20 or 25 which were usual before. This time practically all the national parties took part in the elections. Our Indian National Congress led at the centre by Shrimati Indira Gandhi and in the State by Syed Mir Qasim also took part in the elections. Then there was the Congress (O) to which Shri Shyamnandan Mishra happens to belong, the Jan Sangh, the CPI, Swatantra, the Socialist Party and the Jamaat-e-Islami which is a regional party confined to the Kashmir valley. Compared to the last elections, the contest was more keen and the people took a lot of interest in the election compaign initiated by the various parties.

Once again the people of the State have put their faith in the leadership of the Congress and they have confirmed their confidence in the leadership of Syed Mir Qasim, and they have shown their belief that the Congress will be in position to deliver the goods and fulfil the aspirations of the people. In the Jammu division, there was a keen contest between the Congress and the Jan Sangh, and all the big guns of the Jan Sangh visited that area and actively compaigned for their condidates, but unfortunately, the people once again have rejected the Jan Sangh ideology and programme. They contested more than 30 seats and they got only three.

The point has been made about the emergence of the regional party known as Jamaat-e-Islami in the Kashmir valley. Here I would like to clear one or two points. Firstly, this element came into being as a recognised political party to take part in the elections in the last mid-term poll to the Lok Sabha, and this is the second time that they took part in the elections to the State Assembly. They contested more than 35 seats, but they got only five seats Compared to the mid-term poll to the Lok Sabha, this time the total votes got by the Jamaat-e-Islami was much less than what they got in the mid-term poll. Though it is a matter of concern for us that such communal parties have come up, I am fully confident that there is a strong political leadership available in Jammu and Kashmir and under the overall leadership of Shrimati Indira Gandhi at the centre we shall certainly be able to fight these new communal trends.

There is another good development which has taken place. Mr. Mohiuddin Karra, the Founder-President of the Political Conference of Jammu and Kashmir has been for a number of years pleading for the State's association to Pakistan. Now he has changed his views and he says that Kashmir's accession to India is final and irrevocable. We welcome this change in his views and we hope keeping in view the other political developments which have taken place all over the country, he would further change his views and see that he also contributes to the speedy development of the State. Though he has expressed his confidence in the accesion of the State to India, he says some kind of autonomy should be given to the State. My hon. friend from the DMK who preceded me also spoke about State autonomy. But when I analyse the results of the elections and look at the change in the attitude of the people, I coma to the conclusion that the people do not want to give more autonomy to the States. They only want that whetever programme for speedy economic development is initiated at

the centre, that should be implemented with greater speed in the States by the State Governments. That can only be done if there is a good deal of uniformity in the political and economic programme initiated at the Centre and in the States. As the same time, the State leadership should have full faith in the Central leadership and the Central leadership should have full faith in the State leadership to implement the programmes initiated at the Centre or in the States. Keeping in view these developments and the changes which the people demand, I think a better coordination between the Centre and States is required rather than more State autonomy.

Mr. Mishra was talking about a dialogue with Mr. Bhutto and asked, why not we call President Bhutto to come here or why not our Prime Minister go to Islamabad.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA : Both of them have said that they are prepared to have talks without any pre condition. I asked, what is coming in the way ?

SHRI INDER J. MALHOTRA : It is only you who are coming in the way and nobody else. When you say there should be a talk, you must specify what you mean by talk. Talk regarding what ? There can be no talk about the integrity of the country or the integrity of Jammu and Kashmir. Unless these points are clearly mentioned, and understood, I do not see what useful purpose will be served.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA : Then why does the Prime Minister say that she is prepared to discuss without any pre-condition ?

SHRI INDER J MALHOTRA : I heard you patiently. Please hear me also patiently. Basically we are not opposed to this kind of dialogue. But, before it is done, issues must be clearly understood, and issues should not be allowed to be confused by Pakistan or any other country. We are not interested in keeping the prisoners of war of Pakistan in our country a moment longer than required. At the same time, we ara not prepared to link up the prisoner of war issue with the Kashmir problem. In fact, there is no Kashmir problem today. With the emergence of Bangladesh, even those political leaders who, for a number of years, have been pleading for the States's accession to Pakistan have changed their views today. So, when their is a rapid change coming in those political elements who were earlier pleading for the State's accession to Pakistan, where is the Kashmir issue about which President Bhutto wants to talk ? The only issuer on which we are prepared to talk with Mr. Bhutto are the prisoners of war and the recognition of Bangladesh so that all other connected problems can be solved to the benefit of all.

In the end Sir, I thank you and I once again support the motion of Thanks on the President's Address.

श्री रामसहाय पांडे (राजनन्द गांव) : श्री पीठाधीश जी, आपने बड़ी कृपा की राष्ट्रपति जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन का अवसर दिया, इसके लिये बहुत-बहुत साधुवाद ।

श्रीमन् एक वर्ष के अन्दर हमारे राष्ट्र ने जिस प्रकार लोकतंत्र को शाश्वत जीवन दिया ताकि यह स्थिर हो, एक धारणा दी, मान्यता दी और यह सम्भव हो सका है कि हमारा राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों की अपेक्षा, चाहे अकिंचन हो, साधनों की कमी हो, लेकिन मूलभूत लोकतंत्र प्रणाली प्रथा में हम संसार के किसी भी लोकतान्त्रिक राष्ट्र से पीछे नहीं हैं । इसका उदाहरण स्वयं जनता ने दिया । दो चुनावों के संदर्भ में उसने यह सिद्ध किया कि हम अपनी समस्याओं के प्रति जागरूक हैं, लोकतन्त्र की दृढ़ता के प्रति जागरूक हैं, उसकी प्रस्थापना के लिए जागरूक हैं और जागरूक हैं हम उस दिशा की ओर जाने के लिये जहां समाजवाद है, एकता है, समानता है ।

श्रीमन्, बिखरे हुए राजनीतिक दलों की विचारधाराओं को आप देखें तो सबने मिलकर एक नारा दिया जनता को कि लोकतन्त्र खतरे में है । श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में लोकतन्त्र खतरे में है, आओ, हमारे साथ मिल जाओ और इन्दिरा को हटाओ । श्रीमती इन्दिरा गांधी ने सिर्फ एक नारा दिया था—लोकतन्त्र की दृढ़ता के लिये इस देश में एक बड़ी भारी समस्या है गरीबी हटाने की । हम सारे देश के साथ सम्मवेत होकर इस संकल्प को लेकर गरीबी हटाने की दिशा में बढ़ना चाहते हैं । जनता ने अपना निर्णय

[श्री रामसहाय पांडे]

दिया, श्रीमती इन्दिरा गांधी को बहुमत दिया।

जब राज्यों के चुनाव आये, तब इन्हीं दलों ने यह कहा कि वह तो इन्दिरा जी की हवा थी, अब राज्यों के चुनावों में स्थानीय समस्याओं में जनता उलझेगी और स्थानीय समस्याओं पर श्रीमती इन्दिरा गांधी का प्रभाव नहीं होगा। आपने देखा कि श्रीमती इन्दिरा गांधी का प्रभाव आश्वासन के साथ, विश्वास के साथ, हम कुछ करना चाहते हैं—इस निष्ठा के साथ, सामने आया और जनता ने फिर अपना विश्वास और दृढ़ता प्रकट की और राज्यों में जो निर्वाचन हुए, बड़े प्रचण्ड बहुमत के साथ कांग्रेस का साथ दिया और बड़ी शान्ति के साथ वहां शासन का संचालन हो रहा है। यह दिखाव, यह बिलगाव स्वस्थ परम्परा से बहुत दूर है। यदि विरोधी दल स्वस्थ दृष्टि से सोचें और जनता को भी एक स्वस्थ दृष्टिकोण बनाने के लिये आग्रहित करें तो हमारे लोकतन्त्र की स्वस्थ प्रणाली की ओर एक सुन्दर श्रीगणेश का शुभारम्भ होगा।

16·57 hrs.

[SHRI R. D. BHANDARE *in the Chair.*]

कांग्रेस (जीरो) के विरोधी दल के नेता श्री श्यामनन्दन जी मिश्र अभी यहां पर बैठे हुए थे। कांग्रेस (ओ) की राजनीति स्पष्टतः एक गुस्से की राजनीति थी, घृणा की राजनीति थी, पारस्परिक ईर्ष्या की राजनीति थी। मैं इसके अन्दर नहीं जाना चाहता हूं, उनके पीछे कोई एक सौष्ठ विचार नहीं था, गुस्सा थी, घृणा थी। स्वतन्त्र दल की राजनीति धन्ना सेठों की राजनीति थी। स्वतन्त्र व्यापार करने की सुविधा उनको दी जाय, किसी प्रकार का सरकारी नियन्त्रण न हो, यह उनकी राजनीति थी। एस० एस० पी० की राजनीति दुराग्रह और शठता की थी। उन्होंने कहीं पर किसी भी प्रकार से स्वस्थ वातावरण के निर्माण में कोई योगदान नहीं दिया। सी० पी० एम० की राजनीति हत्या और और विध्वंस की राजनीति थी। पश्चिमी बंगाल में जब तक श्री ज्योतिबसु का रिजीम रहा, हत्यायें, भय, लूट, आगजनी से वातावरण क्षुब्ध रहा। उन्होंने एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी थी जिससे स्वयं जनता के मन में आक्रोश का जन्म हुआ, जनता दुखी थी। इस प्रकार की घटनाओं ने इस चुनाव में सिद्ध कर दिया कि श्रीमती इन्दिरा गांधी ने जो स्वस्थ कार्यक्रम दिया, तो जनता ने भी 216 सीटें देकर उनको प्रचण्ड बहुमत प्रदान किया।

जनसंघ की राजनीति को आज तक समझना बड़ा कठिन है। जनसंघ की राजनीति को यदि अभी मैं कहता कि साम्प्रदायिकवादी नीति है तो श्री हुकमचन्द कछवाय मेरे गले पड़ जाते। अच्छा है कि वह इस समय यहां नहीं है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपना भाषण नाट्यम करके और वाणी-विलास करके समझते थे कि सारा देश उनके साथ है। उनकी राजनीति में राजे-महाराजे आ गये। आपने उनके भाषण में सुना होगा, पराजय के बाद जिस प्रकार गीली आंखों से आंसू टपकाते हुए मरसिया पढ़ रहे थे, कितनी निराशा उनके मन में थी। जनता चाहती है कोई भी राजनीतिक दल हो जो जनता के साथ हो और गरीबी हटाने की बात करे, स्वस्थ परम्पराओं के निर्माण और प्रस्थापन की बात करे तभी जनता उसका साथ देगी। लेकिन राजे-महाराजाओं के झण्डे के नीचे उनकी दीपक से आरती उतारते-उतारते, यदि जनसंघ यह चाहता हो कि वह जनता की दृष्टि में प्रियपात्र बन सकेगा, तो वह कभी नहीं बन सकेगा। महारानी सिंधिया दीपक लेकर समझती थीं कि हमारा बहुमत होगा, प्रीवी पर्स के नाम पर उन्होंने कहा था कि चलो जनता से बडिवट लो। उन्होंने बड़े अहंकार से प्रीवी पर्स के लिये कहा था लेकिन आज न राजे हैं, न महाराजे हैं, न प्रीवी पर्स है, न प्रिवलेज हैं, न प्लेट है, न बिजली की सुविधायें हैं, कहीं कुछ नहीं है। पर्स है, लेकिन उसके अन्दर कुछ नहीं है। थैली है लेकिन पैसा नहीं है। जनता ने राजनीतिक क्षेत्र में उनको उठा कर फेंक दिया। वे अपने बेटे को मुख्य मंत्री बनाना चाहती थीं। उन्होंने कहा था—जनसंघ का प्रचण्ड बहुमत मध्य प्रदेश में होगा। मध्य प्रदेश में प्रचण्ड बहुमत तो

क्या, प्रचण्ड अल्प मत भी नहीं है। जिस क्षेत्र में उनको विशाल विजय मिलती थी, वहां से आज वे स्वयं दस हजार वोटों से जीतीं और उनके तमाम खड़े किये लोग हार गये।

17 hrs.

सी० पी० आई० की राजनीति एक सामयिक राजनीति है। वे समय की गति को पहचानते हैं। यहां पर यदि हम यह न बताये कि हमारी कांग्रेस की क्या नीति है तो उचित नहीं होगा। हमारी कांग्रेस की यथार्थवादी नीति है। लोकतन्त्र में यथार्थवाद की ओर जो बढ़ता है वही आगे बढ़ सकता है, वह शक्ति के साथ राष्ट्र को गति दे सकता है। तो हमारी नीति यथार्थवादी नीति है। देश की आवश्यकतायें क्या थीं, इसको हमने समझा। देशकी जनता क्या चाहती है, वह हमने समझा। अकिंचनता को, निर्धनता को हटाना, रोटी-कपड़े के संस्कार से मंडित करना—उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत्। इस सम्बोधन के साथ उठाना, चलाना, अपने कर्त्तव्य का बोध कराकर लक्ष्य की सिद्धि, क्रिया की सिद्धि की ओर बढ़ाना—यही हमारा लक्ष्य था जिसको जनता ने समझा है।

आर्थिक विकास के सम्बन्ध में राष्ट्रपति जी ने बड़ी सुन्दर बात कही है। एक मूलभूत बात है कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, इसमें सौ में 72 लोग गांवों में रहते हैं। उन्होंने सिंचाई की ओर थोड़ा इशारा किया है। मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि सिंचाई के प्रावधान में हमने बड़ी उदासीनता का व्यवहार किया है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट का प्रिंसिपल यह है कि बायलाजिकली धरती को पानी चाहिए। पानी मिल जाने के बाद हाइब्रिड सीड, फर्टिलाइजर, पेस्टीसाइड्स यह सारे साफिस्टिकेशंस बाद में आते हैं। सबसे पहली आवश्यकता पानी की है। आपने चौथी पंचवर्षीय योजना के अंत तक पचास प्रतिशत सिंचाई का जो प्रावधान किया था उसमें 28 प्रतिशत तक ही पहुंचे। 22 प्रतिशत हम अभी पीछे हैं। इस 22 प्रतिशत के संकल्प को पूरा करने के लिए जिसको पूरा करने में हम पीछे रह गये हैं, 750 करोड़ रुपया हमें चाहिए। हमारे यहां नदी नाले और बड़ी-बड़ी नदियां हैं, पानी की कोई कमी नहीं है। तीन हजार 6 सौ मिलियन एकड़ फीट पानी धरती पर ऊपर से बरसता है। लेकिन सिंचाई के प्रावधान में केवल 150 मिलियन एकड़ फीट पानी आता है। इस प्रकार आपने जितनी योजनाएं बनाई वह अधूरी रह गई। इसलिए मेरा निवेदन है कि फर्स्ट थिंग फर्स्ट को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। सिंचाई की एक नीति होनी चाहिए। नाली, नाले, नदियों को बांधकर जल को खेतों की ओर उन्मुख कर दें तो फिर किसान आपसे कुछ नहीं चाहता। जितना पानी ऊपर से बरसता है वह तो ठीक है। लेकिन टैंक इर्रीगेशन, लिफ्ट इर्रीगेशन, नालों का पानी, नदियों का पानी जो बेकार चला जाता है जिससे सिंचाई नहीं होती है उस सबका प्रावधान कर दिया जाय योजना में। पंचवर्षीय योजना में, मैं आपके माध्यम से श्रीमती इन्दिरा गांधी, प्रधान मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि प्राथमिकता सिंचाई को देनी चाहिए। सिंचाई को प्राथमिकता देने से सेल्फ-जेनरेटिंग एकोनामी का सिलसिला पैदा होगा क्योंकि खेती से जो सामान हम पैदा करते हैं, उससे 79 परसेंट फारेन एक्सचेंज प्राप्त करते हैं। किसान श्रम करता है, फारेन एक्सचेंज अर्न करता है। उसके बाद जो नेशनल इनकम 30 हजार करोड़ की है उसमें आप जो प्राविजन करते हैं वह केवल 15 हजार करोड़ है। जो रुपया आता है वह अग्रेरियन एकोनामी से आता है। किसानी के सेक्टर से आता है। लेकिन आप उसमें जो प्लाऊ बैक करते हैं वह सिर्फ 22 प्रतिशत है। साधारण अर्थ-व्यवस्था का नियम है कि जिस सेक्टर से जितना पैसा आए उतना प्लाऊ बैक होना चाहिए। इन्द्र भगवान की कृपा से तीन चार वर्ष से वर्षा अच्छी हो रही है। 11 करोड़ टन के करीब हमारे यहां अनाज हो रहा है। और अब हम डेफिसिट से प्लेन्टी की ओर शिफ्ट कर रहे हैं, यानी कमी से बहुतायत की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे हमारे यहां 85 लाख कपास की गांठें हो गई तो सवाल उठा कि कैसे खरीदें और कहां रखें? किसान को रेम्युनरेटिव प्राइस देने के लिए हम बाध्य हैं जैसा कि गेहूं के मामले में हमने किया। गेहूं के प्रोक्योरमेंट में किसान को अच्छी कीमत मिले इसके लिए हमने

[श्री रामसहाय पांडे]

प्रावधान किया है। तो अब किसान में सेन्स आफ कांशसनेस, एक आत्म-चेतना का भाव पैदा हो गया है। वह अधिक उत्पादन करना चाहता है। किसान चाहता है कि उसके हाथ सदा मिट्टी में सने रहें। उसको पानी चाहिए। हिन्दुस्तान में जितना भी पानी होता है उसका पांचवां हिस्सा यानी 20 प्रतिशत मध्य प्रदेश को प्राप्त है। लेकिन वहां सिंचाई केवल 6 प्रतिशत है। जिस प्रदेश में इतनी विपुल सम्पत्ति हो, जनसंख्या भी कम हो धरती अधिक हो, किसान अधिक हों, लेकिन वहां पर पानी न हो तो यह एक बड़ी भारी दुर्व्यवस्था और कारण हो सकता है। मैं विशेष निवेदन करना चाहता हूं जैसा कि डा० के० एल० राव ने अपने बयान में कहा था कि मध्य प्रदेश में न रेलें हैं, न यातायात के साधन हैं, न सिंचाई का प्रबन्ध है और न औद्योगीकरण है। केवल एक भिलाई स्टील प्लान्ट है। हम चाहते हैं कि एक कमीशन बना कर जो वहां की नेचुरल सम्पदा है उसका सर्वे कराया जाय। मैं आपका ध्यान बिजली की ओर दिलाना चाहता हूं। कोरवा में कोल बेस्ड थर्मल एलेक्ट्रिक प्लान्ट लगा दिया जाए। रिपोर्ट यह है कि 3 हजार मेगावाट बिजली पैदा करके 6 प्रदेशों को दे सकते है—उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरयाना, राजस्थान और महाराष्ट्र को। कोयले से बनी हुई बिजली हम उनको देंगे। हमसे इन प्रदेशों वाले कोयला मांगते हैं। जब कोयला मंगाते है तो वेगन इंग्रेज होते हैं। उसमें वेगन की सप्लाई में बडी सुविधा होगी। इसलिए कोल बेस्ड थरमल प्लान्ट, जो तीन हजार मेगावाट बिजली पैदा कर सकता है, से हम बिजली सप्लाई करने का दावा करते हैं। इस तरह से कोल बेस्ड फर्टीलाइजर्स प्लान्ट भी है, उसको भी प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

एक समस्या और है जिसका जिक्र मैं इस सभ्यता के युग में करना चाहता हूं और वह है डाकू समस्या। श्रीमन् बंगला देश से हम निपट लिये। उसको स्वतंत्र कराया। पाकिस्तान से युद्ध हुआ, उसमें हम विजेयी हुए। हमारी ख्याति और कीर्ति का सारे संसार में उदय हुआ। आज हमें यह सुनकर बड़ी प्रसन्ता हुई है कि श्री पंत जी बड़ी लगन के साथ इस डाकू समस्या का समाधान करने जा रहे है और तीन मंत्री भी इस कार्य में लगे हैं (**व्यवधान**)।

आप यह देखिये कि डाकुओं की परम्परा कहां से आई। इस परम्परा का जन्म फ्यूडल सोसायटी से हुआ। तीन कांस्टीटुयेन्सीज हैं जहां पर ये डाकू भरे पड़े है। एक है भिंड कांस्टीटुयेन्सी जो कि महाराजा सिंधिया की कास्टीटुयेन्सी है। एक है ग्वालियर की कांस्टीटुयेन्सी, जहां पर वे लोग आ कर शरण लेते हैं। वह कांस्टीटुयेन्सी किस की है? श्री अटल बिहारी बाजपेयी जी की। एक है गुना की कांस्टीटुयेन्सी। वह कांस्टीटुयेन्सी किस की है? वह है श्री माधव राव सिन्धिया की कांस्टीटुयेन्सी। यह वह क्षेत्र है, वह बैल्ट है जो कि डेकायट इन्फेस्टेड हैं और इनके प्रतिनिधि है महारानी सिन्धिया, श्री अटल बिहारी बाजपेयी और श्री माधवराव सिन्धिया। इन राज परिवारों से इनको सहायता मिलती रही है और भिंड की रेवाइन्स में इनको शैल्टर मिलती रही है और ये वही रहते है और जो माल इकट्ठा करके लाते हैं वह ग्वालियर के पैलेस मे इकट्ठा करते है या जो उनके दूसरे फ्यूडल्स है या जो उनके सुबेदार लोग है वहां जमा करते हैं।

इसलिए समस्या के समाधान के लिए आदरणीय जय प्रकाश जी के इस प्रयत्न की मैं सराहना करता हूं। अगर कोई नैतिक विचार पैदा हो, नैतिक आचरण का उदय हो या नैतिकता का भाव हो और यह जो सभ्यता के इस युग में डेकायटी समस्या से जो हम उलझे हुए हैं, इसका कोई समाधान हो, इसके लिए हम श्री के० सी० पंत जी से यह चाहते हैं, उन से यह उपेक्षा करते हैं कि वे इस समस्या के समाधान के लिए कुछ करें। श्री जय प्रकाश जी और अपने बड़े तरुण साथी मुख्य मंत्री श्री प्रकाश चन्द्र सेठी जी से भी हम आशा करते हैं कि कम से कम इस समस्या का स्थायी समाधान कुछ न कुछ होना चाहिए।

इन शब्दों के साथ आप ने जो हमें समय दिया है, उसके लिए बहुत धन्यवाद।

श्री रामचन्द्र विकल (बागपत) : आदरणीय सभापति जी महोदय, मैं श्री अलगेशन द्वारा जो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव रखा हुआ है, उस के समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूं।

सभापति महोदय, इस धन्यवाद प्रस्ताव पर अनेक माननीय सदस्यों के भाषण मुझे यहां सुनने को मिले। मुझे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता श्री गोपालन जी के विचार सुनने का भी मौका मिला। वे प्रजातंत्र और अहिंसा के ऊपर बहुत जोर दे रहे थे और बंगाल के चुनावों के आगे वे नहीं बढ़ सके और वहां की घटनाओं को सुनाते रहे। उस समय मुझे ऐसा मालूम हो रहा था जैसे कोई रत्नाकर वाल्मीकि ऋषि बन गये हों और वही उपमा मुझे याद आती थी उन दिनों जबकि वे भाषण कर रहे थे कि ये महर्षि वाल्मीकि बन गये हैं। उन्होंने अहिंसा और जनतंत्र के बारे में बहुत बहुत बातें यहां पर कहीं। मैं नहीं जान पाया कि उनकी अहिंसा और जनतंत्र के पीछे वास्तविकता क्या थी ? जो उन के भाषण में ये बातें आई वे असली रूप में मुझे नजर नहीं आती। प्रो० हिरेन मुकर्जी ने जो स्वयं भुक्तभोगी हैं और बंगाल के निवासी हैं, बहुत अच्छे शब्दों में उनके भाषण की एक तौर से काट की और बताया कि वास्तविकता से परे कितने उनके विचार हैं और उन का असल रूप दूसरा ही है। प्रो० हिरेन मुकर्जी स्वयं उन बातों के भुक्तभोगी रहे हैं।

सभापति जी, राष्ट्रपति जी के संभाषण पर विरोधी दलों के लोगों ने जो बहुत अधिक जोर दिया वह इस बात पर कि युद्ध के दौरान सारा श्रेय प्रधान मंत्री जी को क्यों मिल गया। इस बात पर उन में कुछ बहुत परेशानी रही और इसी चीज को उन्होंने बहुत ज्यादा कहा। राष्ट्रपति जी ने तीन चार जगहों पर अपने संभाषण में इस बात का जिक्र किया है। उन्होंने कहीं भी एक दल की चर्चा नहीं की। अगर माननीय सदस्य इस भाषण को पढ़ते जैसा कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अन्तिम रूप से कहा, तो उन को वास्तविकता का पता चल जाता। अन्तिम जो पैराग्राफ है, उस में राष्ट्रपति जी ने यह कहा है :

> "सम्मानीय सदस्यो, अन्त में मैं आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि गरीबी के खिलाफ लड़ाई किसी सैनिक कार्रवाई से कम बहादुरी की बात नहीं है। इस महान संघर्ष के लिए कठिन परिश्रम एवं लक्ष्य के प्रति गहन निष्ठा की आवश्यकता है। सतत् परिश्रम एवं त्याग के बिना कभी कोई महान कार्य नहीं हुआ है। मैं इस महान देश के सभी वर्ग के लोगों एवं दलों से निवेदन करता हूं कि युद्ध के समय आप लोगों ने जिस एकता की भावना का प्रदर्शन किया, देश के निर्माण के लिए भी वैसी ही भावना का प्रदर्शन करें।"

यह राष्ट्रपति जी ने स्वयं अपने भाषण में कहा है। सभी दलों से उन्होंने अपील की है, सारे देश की जनता से उन्होंने अपील की हैं और जो सारा श्रेय है वह, उन्होंने यह कोशिश की है, इस देश की तमाम जनता और दलों को दिया है। मैं यह जरूर कह सकता हूँ कि लड़ाई के समय पर जो भावना विरोधी दलों ने इस सदन में और इस सदन के बाहर दिखलाई, उसके लिए वे सराहना के पात्र हैं, उस के लिए हमें उन की सराहना करनी चाहिए। राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में स्वयं उस की सराहना की है। तब इन सब बातों को भूल करके हम उन सारी अच्छी बातों को जो देश हित में हम पीछे कर चुके हैं स्वयं भी भुलाएं या हमारी प्रधान मंत्री जी वे जो कुछ किया है उसको भुलाएं या देश की जनता ने जो काम किये है उनको भी भुलाएं, तो यह चीज न तो विरोधी दलों के हक में ही जानी है और न किसी और दल या राष्ट्र के हक में जाती है। राष्ट्रपति जी ने प्रारम्भ में ही इस बात को कहा है :

> "राष्ट्र एक बहुत बड़ी परीक्षा में खरा उतरा है। बाहरी आक्रमण के मौके पर देश ने बहुत बड़ी एकता, साहस, संवेदनशीलता

[श्री रामचन्द्र विकल]

तथा स्पष्ट दृष्टिकोण का परिचय दिया। इससे संसार को यह स्पष्ट हो गया है कि देश के लोग किस तत्व के बने हैं। बंगला देश के साढ़े सात करोड़ लोगों की आजादी और जिन्दगी खतरे में पड़ गई थी।"

तो राष्ट्रपति जी ने जो प्रारम्भ किया है उस से भी सारे देश की जनता, सारे दलों को और सभी को उन्होंने इस तौर से लिया है जिस से हमारा देश मजबूत रहे।

और तीसरे पैराग्राफ में राष्ट्रपति जी ने कहा है :

"इस कार्य में संसद् ने जो मार्गदर्शन किया, राजनीतिक, राजनीयक तथा सैन्य सम्बन्धी नीति और निर्णयों में सरकार ने जिस विवेक और नेतृत्व का परिचय दिया, प्रशासन के सभी स्तरों पर जो प्रभावकारी कार्य संचालन हुआ··· ।"

यह राष्ट्रपति जी ने संसद के बारे में कहा है जिस में सभी विरोधी दल आ जाते हैं। तो मैं नहीं जान पाया कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण को हमारे मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने सुना नहीं, सुनने भी नहीं दिया किसी को, मगर पढ़ने की भी कोशिश नहीं की। उस भाषण को उन्होंने पढ़ा नहीं वरना वे इस तरह के विचार न रखते (**व्यवधान**) चुनावों के आगे वे बढ़ कर नहीं दिये, चुनाव के आगे कोई विचार सुनने को नहीं मिला। यह मैं राष्ट्रपति जी के भाषण के सम्बन्ध में कह रहा था।

सभापति जी, यश प्रधान मंत्री जी को मिल गया। मैं तो एक आस्तिक व्यक्ति रहा हूं। सभापति जी "हानि, लाभ, जीवन-मरण, यश-अपयश विधि हाथ"। जब यश मिलना था प्रधान मंत्री जी को तो विरोधी दलों को इस मामले में बहुत ज्यादा परेशानी या हैरानी नहीं होनी चाहिए। यश मिला इस बात के लिए कि देश का नेतृत्व संकट काल में इस रूप से किया, इस दृढ़ता से किया, इस दूरदर्शिता से किया, समय के साथ क्या करना चाहिए उस समय के अनुसार प्रधान मंत्री ने देश का नेतृत्व किया। यह स्वाभाविक ही है। हम यश दें या न दें, आज इस देश के विरोधी दल यश दें या न दें लेकिन इस देश की करोड़ों जनता इस बात को कहती है कि प्रधान मंत्री जी साहस, हिम्मत और दूरदर्शिता मे पं० जवाहर लाल नेहरू से भी आगे बढ़ी हुई है। यह गांवों के लोगों की प्रक्रिया मैं आप को बता रहा हूँ और यही एक कारण है कि विरोधी दल के लोग देश की जनता की भावनाओं को पहले तो समझते ही नही थे मगर इन कुछ दिनों में जो हालात हुए उन हालात के पहले वे गावों के गरीब लोगों की भावनाओं को समझ नही पा रहे थे। देश की करोड़ों जनता प्रधान मंत्री जी का आभार मानती है इस बात के लिए कि उन्होंने अपने इस नेतृत्व में देश को हर माने मे सुदृढ़ किया है, हर माने मे स्वावलम्बी किया है, अन्न के मामले मे हमारा देश स्वावलम्बी हुआ है। अमरीका से जो अन्न आता था वह आना बन्द हो गया है। प्रधान मंत्री जी ने बड़े गर्व के साथ देश की जनता से अपील की कि अमरीका गवर्नमेंट अन्न के बदले में हमारे स्वाभिमान को खरीदना चाहेगी या हमारे स्वाभिमान को ठेस लगाएगी, तो प्रधान मंत्री जी ने अनेक बार कहा कि मैं अपने देश की 55 करोड़ जनता से एक वक्त भोजन खाने की अपील करूंगी लेकिन अमरीका के सामने इस देश के स्वाभिमान को बेचने वाली नही हूं। यह कम स्वाभिमान की बात नहीं है। यही कारण है कि आज हमारे देश का सम्मान सारी दुनियां में बढ़ रहा है, हमारा मस्तक ऊँचा हो रहा है और प्रधान मंत्री की हिम्मत की, उनके साहस की, उनके प्रयत्नों की उनकी बहादुरी की प्रशंसा हो रही है।

बंगला देश को मान्यता देने की बात भी थी। वाजपेयी जी आ गए हैं। उन्होंने कहा था कि बंगला देश को मान्यता हमने देर से दी और अगर पहले दे दी होती तो इतना खून खराबा नहीं होता। मैंने उनके इस भाषण को बड़ी शान्ति के साथ सुना था। मैं उनका आदर भी बहुत

करता हूं। जब युद्ध बन्द हो गया तो उन्होंने कहा कि इसको इतनी जल्दी बन्द क्यों कर दिया। यानी खून खराबा पहले भी होना था और बाद में भी होना था। तो इससे अन्तर क्या पड़ा ? लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहता हूँ कि प्रधान मंत्री ने कहा था कि समय आने पर देश की सरकार बंगला देश को मान्यता देगी। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि भारत सब से पहला दुनिया में देश था जिसने बंगला देश को मान्यता दी और भारत द्वारा मान्यता देने के बाद ही आज जो 32-33 देशों ने मान्यता दी है, उन्होंने बंगला देश को वह मान्यता प्रदान की। पहले हमने दी और बाद में उन्होंने दी। हमारा देश इस मामले में दुनिया में अग्रणी रहा और सारी दुनिया ने हमारी बात को माना। पहले किसी देश की हिम्मत नहीं हुई। यह हमारी प्रधान मंत्री की दूरदर्शिता का प्रतीक है और समय की पहचान की बात है। किस समय पर कौन काम होना है, इसको उन्होंने इन दो सालों में अनेक बार दोहराया है। इससे प्रधान मंत्री जी की ख्याति देश में तथा जनता में बढ़ी हैं और उन्होंने किस समय पर कौन सा आप्रेशन करना है सही माने में, उसको करके दिखा दिया है। एक सफल डाक्टर की भांति उन्होंने पहले फोड़े को पकने दिया और तब उसको फोड़ा, तब उसका आप्रेशन किया। बंगला देश को सबसे पहले मान्यता देकर एक उदाहरण उन्होंने दुनिया के सामने रखा और दुनिया ने बाद में उसको मान्यता दी।

अन्न के मामले में देश आत्मनिर्भर हुआ और इससे दुनिया में हमारे देश का मान बढ़ा। बंगला देश और पाकिस्तान की इस लड़ाई को देखा जाए तो मैं सच्चाई के साथ कहना चाहता हूं कि सारी दुनिया में सुरक्षा के सामले में हम आत्म निर्भर नजर आते हैं। लड़ाइयां दो पीछे भी लड़ी गई हैं चीन के साथ और पाकिस्तान के साथ। लेकिन जिस बहादुरी के साथ, जिस हिम्मत के साथ, इस लड़ाई में हमें जीत प्राप्त हुई है, हमारे सैनिकों ने और नेतृत्व ने इस लड़ाई में काम किया है, उससे पता चलता है कि पिछली दोनों लड़ाइयों से हम कुछ आगे गए हैं और सेना और सुरक्षा के मामले में भी हमारा देश आत्म-निर्भर हुआ है। हम अन्न और सुरक्षा के मामले में आत्म निर्भर हुए हैं।

लेकिन जहां हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े हैं वहां यह भी सच है कि हमारे देश की कुछ आर्थिक कठिनाइयां भी हैं, इसमें दो रायें नहीं हैं। गरीबी हटाने का नारा सरकार की तरफ से जरूर लगा और प्रधान मंत्री जी ने इस नारे को दिया। राष्ट्रपति जी ने अपने अभि-भाषण में कहा है कि सारे देश की जिम्मेदारी है, विरोधी दलों की भी जिम्मेदारी हैं कि वह गरीबी मिटाने के काम में सहयोग दें। उन्होंने कहा है कि गरीबी के विरुद्ध लड़ाई किसी युद्ध से कम नही है। इस में हम सबको सहयोग करना चाहिए। लेकिन मैं विरोधी दलों में यह भावना पा रहा हूं कि वे इस नारे का व्यंग्य तो करना चाहते है लेकिन इस काम में वे सहयोग करना नही चाहते। देश की आर्थिक कठिनाइयों में आप सहयोग करना चाहते है तो मैं सच्चाई से कहना चाहता हूँ कि गरीबी हटाने का जो काम है यह एक शायर की उस शायरी से मिलता है :

थमते थमते थमेगे आंसू
रोना है कुछ हंसी नहीं है।

देश की गरीबी धीरे-धीरे मिटेगी, मेहनत के साथ मिटेगी। मेहनत करने वाले को इस देश में साधन और सम्मान जब मिलेगा तभी देश की गरीबी मिटेगी। गरीबी केवल आलोचना से या कुछ लोगों के आगे बढ़ने से मिट जाए, ऐसा मेरा विश्वास कभी नहीं रहा है। इस बात को मैं जवानों के बीच में भी कहता हूं, विद्यार्थियों के बीच में भी कहता हूँ, जनता के बीच में भी कहता हूं। मैं यह कभी नही कहता कि जवानों, तुम्हारे लिए सब चीज हमको मुहैया करनी है। आखिर जिस देश का भविष्य जवानों पर निर्भर करता है तो जवानों का भविष्य किस पर निर्भर करता है, यह समझ में नहीं आता है। मैं जवानों के बीच में यह कहता हूं कि जब सारे देश का भविष्य तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है तो तुम्हारा भविष्य किस पर निर्भर करता है, यह

[श्री रामचन्द्र विकल]

तुम्हें सोचना होगा। जवानों का भविष्य उनके पौरुष पर, उनके पुरुषार्थ पर, उनके अदम्य विश्वास पर, उनके शौर्य पर निर्भर करता है। अगर हम गरीबी मिटाने के नारे का व्यंग्य उड़ाते रहे और लोगों को यह कहते रहे कि यह तो केवल सरकार का काम है तो लोग मेहनत नही करेंगे।

मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे पंजाबी भाई पाकिस्तान से उजड कर आए। उनके पास जमीन नही थी, कारखाने नही थे, ठिकाना नही था, मुसीबतजदा ये लोग थे। उन्होने अपनी आर्थिक समस्या को जिस तरह से हल किया वह भी एक उदाहरण की चीज है। उन्होंने खेती को नमूने के साथ किया। व्यापार किया तो नमूना एक उसका भी पेश किया। फैक्ट्री या इण्डस्ट्री लगाई तो भी पुरुषार्थ के साथ उस काम को किया। उजड़े हुए लोग इस देश में अगर बस सकते है तो बसे हुए लोग क्या पुरुषार्थ नही कर सकते है, यह मेरी समझ मे नही आता है।

मै मानता हूं कि देश से गरीबी को मिटाने के रास्ते में कुछ चीजें हायल है। लेकिन सारी जनता को, सरकार को, विरोधी दल के लोगो को, पुरुषार्थ करने वाले लोगो को, मेहनत करने वाले लोगों को, किसानों और मजदूरो को हमे आदर और सम्मान देना होगा और जब हमने ऐसा किया तभी लोग परिश्रम करेगे। लेकिन आदर और सम्मान आज धन वालों को मिलता है फिर चाहे लाटरी से रुपया कमाया गया हो या जुए से कमाया गया हो या परमिट से कमाया गया हो। लेकिन मेहनत करने वाले को सम्मान नहीं मिलता है। उसको सम्मान मिलना चाहिए।

इस देश में आप किसान की हालत को देखें। मेहनत करने के बावजूद भी उसको अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आज जब उसकी उपज का भाव तय करने की बात आती है तो उन लोगों से ये तय करवाए जाते हैं जो किसान की समस्या को नहीं जानते और लागत खर्च को नही देखते हैं। आप देखिये कि पिछले साल खाद के दाम क्या थे, बीज के दाम क्या थे, औजारों के दाम क्या थे, मजदूरी कितनी मिलती थी और आज क्या है। सब के दाम बढ़े है। खाद पर इस बार टैक्स बढ़ गया है। आज जो भाव तय किये जा रहे हैं वे पिछले साल से भी कम तय किये जा रहे है। मुख्य मंत्रियो का सम्मेलन होने वाला है। मैं निवेदन करता हूं कि भाव किसान के लागत मूल्य, मेहनत और चीजो के दामों को देकर तय आप करें ताकि देश का उत्पादन बढ़े और देश मालदार और खुशहाल हो।

इन शब्दो के साथ मे जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा गया है, उसका समर्थन करता हू।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर) मै एक औचित्य का प्रश्न उठाना चाहता हू। आप देख रहे है कि सदन मे मन्त्रिमडल के स्तर का कोई मंत्री नही है। मै जिस दिन बोला था उस दिन भी इसको उठाना चाहता था लेकिन चूकि मुझे स्वयं बोलना था इस वास्ते मैने इसको नही उठाया। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा के समय कोई कैबिनेट स्तर का मत्री सदन मे नही रहेगा क्या यह तय हो गया है? आज तक ऐसा कभी नही हुआ। आप सदन के पुराने मैम्बर हैं। मुझे भी सदन का तीसरी बार मैम्बर बनने का दुर्भाग्य या सौभाग्य मिला है।

MR. CHAIRMAN: He has raised his voice. I will convey it to Government.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: यह एक तरीका बन गया है। मंत्रिमंडल का कोई सदस्य यहां बैठ नहीं सकता है? क्या राष्ट्रपति जी के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने का यह तरीका है?

MR CHAIRMAN: Note has been taken.

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur): By whom? Not even the Minister of Parliamentary Affairs is here. We are going to report to the President tomorrow.

THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY

AFFAIRS (SHRI B. SHANKARANAND) : Shri Vajpayee has come into the House just now. Perhaps he may not know that the Prime Minister herself was present here till a few minutes ago.

MR. CHAIRMAN : Shri Kartik Oraon.

SHRI MADHURYYA HALDAR (Mathurapur) : On a point of order. There is no quorum in the House.

MR. CHAIRMAN : The bell is being rung.....

MR. CHAIRMAN : Now, there is quorum.

SHRI KARTIK ORAON (Lohardaga) : Mr. Chairman, Sir, I rise to support the Motion of Thanks on the President's Address.

AN HON. MEMBER : Why ? (*Interruption*).

SHRI KARTIK ORAON : Whereas Mr. Atal Bihari Vajpayee has started with the concluding remarks of the President, I will start with him. Here is a letter which he has written to Raj Bahadurji on the day when the Prime Minister was to be felicitated by the Members of Parliament (*Interruption*) My point is, while I do not mean anything against anybody, I just want to let the House know that when an hon. Member says something, he should mean it. That is my point. He says, ...

SHRI JYOTIRMOY BOSU : Sir, on a point of order.

MR. CHAIRMAN : What is the point of order ?

SHRI JYOTIRMOY BOSU : He was persuading another Member not to spell out something.

MR. CHAIRMAN : It is not a point of order.

SHRI JYOTIRMOY BOSU : It is very much a point of order, with all my deference to you, Sir.

श्री कार्तिक उरांव : "प्रिय राजबहादुर जी, मुझे खेद है कि मैं अभिनन्दन समारोह में शामिल नहीं हो सकूंगा। पूर्व-निश्चित कार्यक्रम के अनुसार मैं बम्बई जा रहा हूं, अनुपस्थिति के लिए क्षमा चाहता हूं।

स्वाधीन बंगला देश का जन्म और इस युद्ध में भारत की महान विजय युग परिवर्तनकारी घटनाएं हैं। ऐसी गौरव पूर्ण घटनाएं हमारे राष्ट्रीय जीवन में पिछली अनेक शताब्दियों में नही घटीं। गत 14 दिन में जो कुछ हुआ है, वह भारतीय इतिहास का एक सुनहरी पृष्ठ है।"

कितना खूबसूरत है !

'इस पृष्ठ पर हमारे जवानों के पराक्रम और शौर्य की गाथा अंकित है। सारे संघर्ष को सफलता के स्वर्णिम शिखर तक ले जाने का श्रेय यदि किसी एक व्यक्ति को दिया जा सकता है, तो वह है हमारी प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी।"

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैंने कहा है, 'यदि किसी एक व्यक्ति।"

श्री कार्तिक उरांव : "उन्होंने इतिहास को बदल डाला है, जो कुछ कहा था, उसे करके दिखा दिया है। विदेश-यात्रा पर जाने से पूर्व प्रधान मंत्री जी ने मुझे मिलने के लिए बुलाया था। उस समय जो बातें हुई, वह मैं आजीवन याद रखूंगा।..."

17.32 hrs.

[SHRI K. N. TIWARI *in the chair*]

What I really wanted to drive at was that when a person of the stature of Shri Atal Bihari Vajpayee was saying something, I think that he meant something ; that when he speaks something he means something. And he is on record ; he cannot deny that. He has rightly put all the credit on the Prime Minister and is very much overjoyed by his doing so. While I was hearing his speech, I was a little surprised that all the time, he was indulging in sabre-rattling and mudslinging, setting one party against another party.

My point is that our Parliament should now raise its stature to such heights that if

[Shri Kartika Oraon]

and when the official Benches do something good from the Government Benches, the Opposition should support it wholeheartedly. Similarly if ever we find something wrong in the Congress Benches, we should point out that to the Government. That should be the spirit of this House, Therefore, when he says, with all his appreciation, that when Gen. Manekshaw mentioned that if the war had continued for five days more, then Pakistan would have been crippled .....

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : I quoted Gen. Manekshaw.

SHRI KARTIK ORAON : Yes ; but whatever you had said, you have contradicted your own statement. You say, Mr, Kumarmanglam said something about delayed recognition of Bangla Desh My point is this. When Members of Parliament start speaking with two voices, where will the poor people of the Villages go ? We should try to speak what we see and we should have belief and conviction in what we say. Therefore, I negative the entire thing said by him in the House-everything.

The Opposition parties took up some portion of the President's Address and says here is a lacuna. They should have in fact talked about how concrete shape should be given to the slogan of *garibi hatao*. Instead. they have been saying that somebody indulged in corrupt and bogus voting and this and that. Let me say that everybody had done something Wrong. It is only a question of degree. Everybody was competing with each other. Let us now put our minds together and find out ways and means so that no such thing is tolerated.

Here comes the law and order problem. We have to develop the national character in the country. I know Mr. Bosu is here I was moving about in Calcutta immediately after the mid-term poll of Lok Sabha in 1971. People said that everywhere Indira wave was there she was so popular in that area too that they would have all voted for Congress Party in 1971 and almost all the Lok Sabha seats from West Bengal would have gone to the Congress but that they had, 12,000 or 14,000 bogus votes in every Assembly Constituency and some of the booths were completely captured. Therefore there is no point in sabre-rattling now and saying that we are responsible for bogus voting, Try to search your hearts before you criticise us.

Some of the good things had been highlighted in the President's Address but here they come forward and say that this is bad and that is bad. We know we have fought a battle of the ballots. Then there was the battle of bullets, Now we have to start the battle of the bellies. Do you think the slogan *garibi hatao* is a misnomer ? You belong to India and you know that there are people in the country who do not have two square meals a day. Do you want that such a situation should be prepetuated in India. It should not be ? Therefore, I say that there should be one masterplan for the whole of India, for uniform system of irrigation all over the country and also a uniform network of roads all over the country. There should be industries everywhere so that nobody could complain that he has not got industries. They should follow the Industrial Policy Resolution of 1956 everywhere. When big projects are constructed, people in that area should get employment first.

SHRI JYOTIRMOY BOSU : You have violated it a number of times.

SHRI KARTIK ORAON : You have also participated in it. With such a network of irrigation and road communications and industrial development, people's confidence would be generated. We are in a different India today, on India which is committed to meet all the basic requirements of the human beings.

We are very conscious of Bangla Desh, but let us understand that Bangla Desh is not only a country, but a state of affairs also where the less privileged people, the weaker sections of the people, are exploited by the more powerful ones Let us see that even in India today there are many Bangla Deshes. We should try to remove from them fears of exploitation also ; they should also be liberated. That is the task before us,

For instance, in Chottanagpur and Santhal Pangana area there are lots of industries, all big industries like the Heavy Engineering Corporation, Hindustan Steel, NCDC, Bokaro etc , but what do the people in this area get ? Nothing. This is a case of Bangla Desh. This is a violation of the Industrial Policy Resolution of 1956. I am only trying merely

to point out the mistakes that the Government is making, and this is not a criticism of the Government.

In the Chota Nagpur area, a lot of tribal people live. Under the Chota Nagpur Tenancy Act, no tribal land can be transferred to a non-tribal. This Act, under section 46(3) prohibits any civil, criminal or revenue court from recognising transfers of lands in contravention of this Act. But after independence, these poor tribals have lost more lands than they have gained. There are some lacunae in this Act also. There is a provision under which land can be transferred with the permission of the Deputy Commissioner. Section 49 permits transfer of tribal lands for the following purposes,namely,charitable, religious, education, industrial, irrigation, building, access to land used or required for any of these purposes, mining etc. I can tell you that lands have been given to all the big projects by the tribals, but they are not getting jobs in them. They are refugees in their own homes. Recently there was the case of the Accountant General Employees' Housing Cooperative Society who acquired about a few hundred acres of land belonging to the tribals After building houses, they have sub-let them or they have sold them at exorbitant prices to big business magnates Now they are claiming another lot of a few hundred acres of land for the Co-operative Society. Is this not an indirect way of grabbing land ? We should not tolerate this.

Only the other day, on 23rd March, I and my friend Mr. P. K. Ghosh, M. P. saw the Chief Minister, Mr. Kedar Pandey and requested him that this sort of thing should be stopped. The tribal people, hoping that they would have some bright days, overwhelmingly voted for the Congress Party, but immediately after the elections, this is what is happening. We pointed this out to the Chief Minifter and he asked the Deputy Commissioner to stop payment of compensation until he had examined it in detail. Some compensations have been paid to the tribals, but how ? At the time of payment in the land aquisition office, they were made completely drunk and everybody was paid Rs. 800 or Rs. 1000 less. In one particular case, a priest who was supposed to have received Rs. 13,900, was paid only Rs. 900 ! They were completely not the way to have *garibi hatao*. This is *garib ko hatao*, We must be conscious of the various problems facing our country, and try to solve them. Even though we have not been able to solve the tribal problems for the last 25 years, it is never to late. Our Government should say, "Look here, Mr. Deputy Commissioner or Chairman, if you do not deliver the goods you should get out." Government should tell them, "Deliver the goods or get out !" That is the way in which we can make these projects yield more resources. They should have given us an annual dividend of Rs. 500 crores by now and we are losing that money. This is the bottleneck. This is not the way to solve the *garibi hatao* problem.

Now we have our family planning programme and say that the number of children should not exceed three. If there are 5 members in a family, at the rate of Rs. 3 per head per day, it comes to Rs. 450 or Rs. 500 a month. So, every family must get a minimum of Rs. 500 a month. That is the only way in which you could generate confidence in the people. Today people are getting Rs.100 or even less. It should be increased to Rs. 500 That is the basic minimum that people must get. Only then the slogan of *garibi hatao* will be more meaningful. People have waited long enough and they cannot be satisfied with more slogans. They have given the massive mandate to one particular party because our Prime Minister had the quality to inspire confidence into the minds of the people. That is the quality of leadership. A leader is one who must belong to the masses, who must have good intentions and who should not try to lose temper. Our Prime Minister has established that she alone can decide the destiny of India. The opposition parties were demanding recognition of Bangla Desh for a long time. Supposing we had recognised Bangla Desh earlier, China and America would have come to this country and there would have been a world war in this country. This great lady knows how to calculate and how to do things at the proper time. She dissolved the Lok Sabha because she realised that with a slender majority, no drastic action was possible.....

(व्यवधान) खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे, वह हालत आज इनकी हो रही है ।

MR. CHAIRMAN : He should conclude.

SHRI KARTIK ORAON : Yes. Sir. I referred to one case in Chotanagpur. That must be looked into. The tribal problem and the problem regarding the restoration of Tana Bhagat lands must be solved. Tribals from whom land have been seized illegally should be given back their lands.

With these words, I whole-heartedly support the Motion of Thanks.

श्री रुद्रप्रताप सिंह (बाराबंकी) : मान्यवर, मैं आप का हृदय के धरातल से आभारी हूं जो आपने मुझ को राष्ट्रपति के अभिभाषण जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचारो को प्रकट करने का अवसर दिया ।

मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण के सम्बन्ध मे जो धन्यवाद का प्रस्ताव यहा पर प्रस्तुत किया गया है, उसका समर्थन करने के लिए खडा हुआ हूं—श्रीमन्,

आदमी वह है जो धरा का भार कन्धो पर उठाये,
बांट दे जग को, न अमृत बून्द अधरों को लगाये,
है जरूरत आज ऐसे आदमी की विश्व को फिर,
विश्व का विष-सिन्धु पी जाये, मगर हिचकी न आये।

ऐसी महान नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी की प्रजातान्त्रिक, समाजवादी, धर्मनिर्पेक्षता की नीतियों वाली सरकार के सम्बन्ध मे राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण हुआ है, उसका मैं हृदय से स्वागत करता हूं ।

श्रीमन्, भारत की प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गाधी के नेतृत्व में सम्पूर्ण देश की समस्त जनता का कितना अटूट विश्वास है कि देश के लोक सभा के मध्यावधि निर्वाचनों मे, बंगला देश के स्वाधीनता संग्राम में और अभी देश भर में हुए विधान सभाओं के चुनावों के परिणामों से हम देख चुके है और जनता का विश्वास है कि उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ऐसी नीतियाँ निर्धारित करेगी, ऐसे सिद्धान्त बनायेगी जिससे देश के अन्दर सामाजिक न्याय की स्थापना होगी और आर्थिक विषमता समाप्त होगी । साथ ही साथ देश विकास की दिशा में अग्रसर होगा और

श्रीमन्, प्रसन्नता की बात है कि सरकार देश में सामाजिक संरचना के कार्य में लगी हुई है और उसने भारत के संविधान मे संशोधन कर के देश में जो दो प्रकार की नागरिकता थी, उस को समाप्त किया । एक और जनसाधारण की नागरिकता और दूसरी ओर देश के भूतपूर्व देशी नरेशो की नागरिकता, दोनो मे बहुत अन्तर था । हमारी जनप्रिय सरकार ने यह निर्णय लिया और उसके पश्चात् उनकी थैलिया और उनके विशेषाधिकार समाप्त किए । यह देश के अन्दर सामाजिक संरचना की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था और एक आधारशिला थी हमारे देश के सामाजिक न्याय की ।

हम सरकार से इस बात का अनुरोध करना चाहते है कि अगर सरकार चाहती है कि देश में सचमुच समाजवाद की स्थापना हो, तो उसके लिए आवश्यक यह है कि देश के अन्दर जाति रहित, वर्ग रहित समाज की रचना की जाय और इसके लिए आवश्यक है, बल्कि अनिवार्य है कि देश के अन्दर जितने भी नागरिक है उनके नाम के पीछे अथवा पहले वर्ग सूचक अथवा जाति सूचक शब्दो का प्रयोग न हो, उस पर निश्चित रूप से प्रतिबन्ध लगाना चाहिये । यह हमारे समाजवादी समाज की संरचना मे बहुत बाधक है ।

साथ ही साथ अगर हम चाहते है कि देश मे समाजवादी समाज की व्यवस्था हो तो हमें अन्तर्जातीय विवाह को अधिक से अधिक प्रोत्साहित करना होगा । देश की जो पिछड़ी हुई जातियां है, हरिजन जातिया है और जो महिलायें है उन्हे सिद्धान्त रूप मे ही नही, अपितु व्यवहार रूप में भी समानता का दर्जा दिलाना होगा ।

श्रीमन्, प्रसन्नता की बात है कि सरकार भूमि सुधार के कार्यक्रमों को तेजी से लागू करना चाहती है । मै आशा करता हूं कि सरकार इन नीतियों में इस प्रकार की व्यवस्था करेगी जिससे समस्त देश के लिये एकरूपता की नीति अपनाई जाय । साथ ही साथ मेरा यह भी सुझाव है कि

वह देश के निर्बल वर्ग को, हरिजन और पिछड़ी जातियों को, ऐसे परिवारों को जो निर्धन परिवार हैं, उनको वह भूमि मिलनी चाहिये, क्योंकि अब तक का जो अनुभव रहा है वह इसके कुछ विपरीत रहा है।

श्रीमन्, हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। हम चाहते हैं कि देश के अन्दर—देश को आत्म निर्भर बनाने के लिए कृषि की उन्नति हो। इस की उन्नति के लिए सिंचाई, खाद और नये बीजों की सुविधायें अधिक से अधिक किसानों को देने की आवश्यकता है। श्रीमन्, मेरा विश्वास है कि श्रीमति इन्दिरा गांधी की जनप्रिय सरकार शीघ्र ही कोई ऐसा कानून भी बनायेगी जिससे शहरी सम्पत्ति का भी सीमांकन हो। हम चाहते हैं कि उसके लिए 3 लाख तक की सीमा की आवश्यकता है। यह एक उचित निर्णय होगा और इसके द्वारा हम सचमूच समाजवाद की दिशा में एक ठोस कदम उठा सकेंगे।

मैं दो शब्द उद्योगों के सम्बन्ध में भी कहना चाहता हूं। समाजवाद की स्थापना के लिए आवश्यक है कि सरकार स्वयं उद्योगों के क्षेत्र में आगे बढ़े और बड़े-बड़े उद्योगों की स्थापना करे। साथ ही साथ देश में जो बड़े उद्योग हैं, उनको सरकार स्वयं अपने नियन्त्रण में ले, उनका राष्ट्रीकरण करे और उनसे होने वाली आमदनी को देश के विकास में, देश के धनी और निर्बल वर्ग में जो असन्तुलन है, उसको सन्तुलित करने की दिशा में लगाये। इसी दिशा में मैं सरकार को पुनः याद दिलाना चाहता हूं कि लोक सभा के मध्यावधि निर्वाचन के वक्त जनता ने उस समय जो आदेश दिया था, उनमें एक आदेश यह भी था कि सरकार चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण करेगी। हमें विश्वास है कि हमारी जनप्रिय सरकार शीघ्र ही चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण करेगी, जिससे देश भर के जो चन्द पूंजीपति परिवार, जो देश के कृषकों का शोषण कर रहे हैं, उनके रक्त को चूस रहे हैं, वह स्थिति समाप्त हो सके।

इन्दिरा गांधी देश में तेजी से समाजवाद की रचना करना चाहती हैं। परन्तु देश की वर्तमान नौकरशाही के द्वारा उसमें कठिनाई आ रही है। हम जानते हैं कि हम जिन समाजवादी नीतियों को अपनाते हैं, उनके कार्यान्वयन में देश की अफसरशाही, नौकरशाही बहुत बड़ी बाधा हमारे सामने स्थापित किये हुए हैं। देश में समाजवाद की स्थापना तभी होगी जब सरकार इस बात की व्यवस्था कर दे कि कानून के द्वारा देश के अन्दर किसी परिवार की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी जाय कि इससे अधिक सम्पत्ति किसी भी परिवार के पास नहीं होगी—चाहे नेता हो, सर्विस में हो, व्यवसायी हो या कृषक हो। यह सभी पर लागू होना चाहिये।

अन्त में मैं विदेश नीति के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। मैं प्रधान मंत्री जी को उनकी विदेश नीति के सम्बन्ध में विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं। इस विदेश नीति से हमारे मित्र देशों की संख्या बढ़ रही है, देशों से मतभेद दूर हो रहे हैं। सोवियत रूस और बंगला देश के साथ जो मैत्री सम्बन्ध हुए हैं, वे बहुत ही महत्त्वपूर्ण हैं और जिनकी सर्वत्र प्रशंसा हो रही है। मुझको अभी हाल में भारत के प्रतिनिधि के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ के महाअधिवेशन में जाने का अवसर मिला था। वहां भी मैंने अनुभव किया कि भारतवर्ष ने जनतंत्र और धर्मनिर्पेक्षता की दिशा में जो कदम उठाये हैं, उससे भारत का गौरव न केवल भारत में, एशिया में, बल्कि विश्व के समुदायों में बहुत ऊंचा उठा है।

सदन के सम्मानित विरोधी दलों के नेताओं ने पिछले चुनावों की निष्पक्षता के बारे में जो बातें कही हैं, मैं केवल एक बात कह कर समाप्त करना चाहता हूं। मुझको अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने पिछले चुनावों में अपना प्रतिनिधि बना कर ग्वालियर सम्भाग में भेजा था। वहां पर मुझे जिला मुरैना के शेवपुर क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने एक पत्र दिया था, जिसके अनुसार जनसंघ पार्टी ने चुनावों में डाकुओं का सहारा लेकर हमारे कार्यकर्त्ताओं की हत्या का प्रयास कराया था।

[श्री रुद्र प्रताप सिंह]

हमारे विरोधी दलों के सम्मानित सदस्यों ने जो विचार यहां पर प्रकट किये हैं, मेरी समझ में वे इस बात से सहमत हैं कि जो हमारी नीतियां हैं, उनको आगे बढ़ाया जाय। उनको केवल इस बात का संदेह है कि हम अपनी नीतियों को आगे बढ़ा सकेंगे अथवा नहीं। मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ—

> क्या खबर है कोशिशे नाकाम ही काम आजाये,
>
> मेरे आगाज पे हसना, मगर अन्जाम के बाद।

इन शब्दों के साथ मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण का हृदय से समर्थन करता हूं और आपको पुनः धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय : चूंकि यह अनाउन्स हो चुका है कि कल प्राइम मिनिस्टर जवाब देंगी, इस लिए अब मैं किसी दूसरे को बुलाने मे असमर्थ हूं। श्री राज बहादुर।

---

18 hrs.

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE
NINTH REPORT

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI RAJ BAHADUR) : I beg to present the Ninth Report of the Business Advisory Committee.

MOTION OF THANKS ON PRESIDENT'S ADDRESS—*Contd.*

श्री शिवनाथ सिंह (झुंझुनू) : सभापति जी, राष्ट्रपति जी ने पिछले 12 महीनों में हमारे देश में जो खास-खास बातें होती हैं उनकी ओर संकेत किया है। हमारी परराष्ट्र नीति के सम्बन्ध में और हमारे देश के अन्दर बहादुरों ने जो बहादुरी दिखाई उसके सम्बन्ध में उल्लेख किया है। अन्त- राष्ट्रीय जगत में आज हमारे देश का जितना मान बढ़ा है उतना पहले कभी नहीं बढ़ा था। आज दुनिया की सभी ताकतें हमें इस बात से आंकने लग गई है कि हिन्दुस्तान एक बहुत बड़ी ताकत बन गया है। यह जो सारा श्रेय है वह किसको देना चाहते है? हमारे जनसंघ के नेता श्री वाजपेयी जी कहते है कि पावर का कंसेन्ट्रेशन बहुत हो गया है। मै निवेदन करना चाहूँगा कि पावर का कंसेन्ट्रेशन किसने दिया है? देश की करोडों जनता ने दिया है। इस बात का श्रेय भी हम जनता को देना चाहें तो इसमें कोई दूसरी बात नही है। आज हमारे देश की प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गाधी जिस प्रकार की नीति पर चल रही है, उसपर समूचे देश को विश्वास है। आप कहते है कि कांग्रेस ने जो बहुमत लिया वह गलत तरीके से लिया। लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि 1967 के चुनावो के बाद विरोधी दलों का जो रवैया था वही इसके लिए जिम्मेदार है कि कांग्रेस को प्रबल बहुमत मिला।

राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कहा है कि पिछले महीनों मे जो घटनाएं घटी हैं उनसे हमारे देश का गौरव बढ़ा है। राष्ट्रपति जी ने बहुत सी बातो की तरफ संकेत किया है लेकिन कुछ ऐसे मुद्दो की तरफ मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं जो और होने चाहिए। एक तो हमारा जो खेती का उत्पादन है उसके व्यापार का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए क्योंकि आज भी किसानों को वाजिब कीमत नहीं मिलती है। आज हमारी सरकार की जो नीति है वह दोषपूर्ण है और उससे किसान को नुकसान होता है। इससे खेती का उत्पादन आगे घटने वाला है। इसलिए जितने भी फूडग्रेन्स है, जितनी खेती की पैदावार है उसका राष्ट्रीयकरण हो।

दूसरे शिक्षा की प्रणाली में, मैं बार-बार कहता हूं, सुधार होना चाहिए। लेकिन कोई कांक्रीट चीज हमारे सामने नहीं आ रही है शिक्षा में इस तरह का सुधार हो जिसमे कि निश्चित लाइन पर हम चल सकें।

तीसरे, देश के जो पिछड़े हिस्से हैं उनका डेवलपमेंट हो। जो हमारे

अफेक्टड एरियाज है उनको कट्रोल करने के लिए आल इण्डिया बेसिस पर विचार करने के लिए कमीशन बनाया जाय। जितने डेजर्ट के भाग हैं उनका डेजर्ट मिटाने के लिए और जहां फ्लड्स होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए यह आवश्यक है।

आखिरी बात यह है कि हमारे यहां ग्राम पंचायत समिति और जिला परिषदें बनी है। एक समय था जब कि हम सत्ता के विकेन्द्रीकरण की ओर जा रहे थे। लेकिन पिछले आठ दस साल मे उनका जो नक्शा हमारे सामने आया है उसका हमे अध्ययन करना चाहिए, उस पर री-थिंकिग होनी चाहिए। हमारी पचायतें, पंचायत समितियों और जिला परिषदो का क्या रूप होना चाहिए उसपर ध्यान देना चाहिए। मेरी ऐसी मान्यता है कि एक पंचायत और एक कोआपरेटिव सोसाइटी इस प्रकार की यूनिट बनाई जाय जो अपने अन्दर सेल्फ सफिश्येंट हो और एक वायबल यूनिट बन सके। दस पन्द्रह हजार की आबादी पर एक पंचायत बने और एक को-आपरेटिव सोसायटी बने ताकि गांवों के विकास की ओर हम अपना ध्यान लगा सकें।

इन शब्दो के साथ मै राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव उपस्थित हुआ है उसका समर्थन करता हूं।

MR. CHAIRMAN : The House now stands adjourned to meet again at 11 A M. tomorrow.

18.04 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, April 4, 1972/ Chaitra 15, 1894 (Saka)

Printed at Shahdara Printing Press, K-18, Navin Shahdara, Delhi-32. 3-4-1972